घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 68- बुधवार 07- जनवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सीएक्यूएम को लगाई फटकार

कहा...कर्तव्य निभाने में रहे असफल

नई दिल्ली,06 जनवरी 2026। दिल्ली-एनसीआर में जारी वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। जिसमें शीर्ष अदालत ने दिल्ली बॉर्डर पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या हटाने के मुद्दे पर 2 महीने की मोहलत मांगने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को कर्तव्य निभाने में असफल रहने पर फटकार लगाई है। वहीं सीएक्यूएम की दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद टोल प्लाजा को हटाने या अस्थायी रूप से बंद करने की मांग को ठुकरा दिया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) दिल्ली बॉर्डर पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या हटाने के मुद्दे पर 2 महीने का समय मांगा था। जिस पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ठुकरा दिया और कहा कि आयोग अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा है। वहीं अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को चरणबद्ध तरीके से लंबे समय के समाधानों पर विचार करना शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के रुख से प्रभावित हुए बिना टोल प्लाजा के मुद्दे पर विचार करेगा। इसी के साथ दो हफ्ते में विशेषज्ञों की बैठक बुलाने और बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारणों पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री कलमाड़ी का 81 की उम्र में निधन,एयरफोर्स में पायलट थे

पुणे,06 जनवरी 2026। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाड़ी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 81 साल के थे। कलमाड़ी को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। कलमाड़ी के आधिकारिक कार्यालय के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे तक कलमाड़ी हाउस एरंडवणे में रखा जाएगा। अंतिम संस्कार दोपहर 3.30 बजे वैकुंठ श्मशान पुणे में होगा। सुरेश शामराव कलमाड़ी का जन्म 1 मई 1944 को हुआ था। कलमाड़ी पुणे लोकसभा सीट से 3 बार सांसद चुने गए। राजनीति के साथ-साथ वे खेल प्रशासन के लिए भी जाने जाते रहे। भारतीय ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष थे। 2010 में दिल्ली में हुए ग्लोबल इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के चेयरमैन भी थे। कलमाड़ी ने रेल राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया था।

सोनिया गांधी तबीयत खराब होने पर सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती,स्वास्थ्य स्थिर

नई दिल्ली,06 जनवरी 2026। कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को तबीयत खराब होने के चलते दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया था। फिलहाल उन्हें चेस्ट फिजिशियन की निगरानी में रखा गया है। सर गंगा राम अस्पताल ने मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में बताया कि सोनिया गांधी को सोमवार रात अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप ने कहा कि जांच में पाया गया कि ठंड और प्रदूषण के कारण उनका ब्रॉन्कियल अस्थमा हल्का बढ़ गया था। एहतियातन उन्हें आगे की निगरानी और उपचार के लिए भर्ती किया गया। अस्पताल ने बताया कि उनकी स्थिति बिल्कुल स्थिर है और वह उपचार पर अच्छी प्रतिक्रिया दे रही हैं। उन्हें एंटीबायोटिक्स और अन्य सहायक दवाओं से इलाज दिया जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी छुट्टी का निर्णय उनके स्वास्थ्य में प्रगति को देखते हुए एक-दो दिन में लिया जाएगा।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बन कर तैयार आरडीएसओ ने शुरू किये अंतिम परीक्षण

जींद,06 जनवरी 2026। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन बनकर तैयार हो गयी है और इसे पटरी पर उतारने से पहले रेलवे की तकनीकी टीम ने मानकों के आधार पर अंतिम परीक्षण शुरू कर दिये हैं। लखनऊ स्थित रेलवे के अभिकल्प, विकास एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) के तकनीकी अधिकारी फिलहाल ट्रेन संचालन को लेकर हर बारीक पहलू पर काम कर रहे हैं। इस विशेषज्ञ टीम ने ट्रेन की टेस्टिंग की। टीम का मुख्य फोकस पावर कार और उससे जुड़े सुरक्षा एवं नियंत्रण उपकरणों पर रहा। स्पीड सेंसर, कंट्रोल सिस्टम को अलग-अलग गति पर परखा गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेन निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित रूप से संचालित हो सके। टेस्टिंग के दौरान ट्रेन को धीमी और मध्यम गति पर चला कर उपकरणों की कार्यक्षमता को रिकार्ड किया गया। इसके अलावा ट्रेन के पायदानों की मजबूती और ऊंचाई की भी जांच की गई। उत्तर रेलवे के अधिकारियों के अनुसार हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलाई जाने वाली इस ट्रेन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस ट्रेन को ईंधन आपूर्ति के लिए जींद में स्थापित किए गए हाइड्रोजन प्लांट को अंतिम कमीशनिंग एवं नियमित संचालन के दौरान स्थिर और निर्बाध 11 केवी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ हाइब्रिड मोड में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्लांट की वर्तमान विद्युत आपूर्ति स्थिति, बैकअप व्यवस्थाओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए।

यूपी एसआईआर...यूपी में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता

ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ नाम कटे...इनमें 46 लाख मृत लोगों के नाम

नई दिल्ली,06 जनवरी 2026। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। इसमें 2.89 करोड़ (18 फीसदी) नाम कट गए हैं। इनमें 46.23 लाख मृत, 2.17 करोड़ लोग शिफ्टेड और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर थे, अब 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं।

मतलब- हर पांचवां वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख, जबकि ललितपुर में सबसे कम 95 हजार लोगों के नाम कटे। वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर

ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। जिन लोगों के नाम नहीं हैं, वे 6 फरवरी तक दावे-आपत्तियां कर सकते हैं। फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। दावे के लिए फॉर्म 6 और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरे जाएंगे। इसकी फीस नहीं लगेगी। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर- 1950 जारी किया है, जहां से सहायता ली जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए आयोग ने विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई है।

6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा- मतदाताओं का गुस्सा आक्रोश बनकर आंदोलन का रूप ले ले, चुनाव आयोग एसआईआर से कटे वैध नामों के लिए संज्ञान लेकर मतदाता सूची दुरुस्त कराए। यूपी से पहले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आ चुकी है। इनमें 3.69 करोड़ वोटर्स के नाम हटे हैं। मध्यप्रदेश में 42.74 लाख, छत्तीसगढ़ में 27.34 लाख, केरल में 24.08 लाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 3.10 लाख वोटर्स, पश्चिम बंगाल में 58.20 लाख, राजस्थान में 41.85 लाख, गोवा में 11.85 लाख, पुडुचेरी में 1.03 लाख, लक्षद्वीप में 1,616, तमिलनाडु में 97 लाख, गुजरात में 73 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं।

एआई सेक्टर में जॉब ग्रोथ रेट 33 फीसदी,इसकी पांचों लेयर में आ रहा बड़ा निवेश: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली,06 जनवरी 2026। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश के सभी पांच एआई लेयर्स में बड़े निवेश आ रहे हैं। इस वर्ष ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में आयोजित होगा, जो पहले ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस में हो चुका है। मोदी सरकार ने भारत को दुनिया भर में एक बड़ा टेक्नोलॉजी हब बनाया है। वैष्णव ने मंगलवार को जयपुर में आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल समिट की तैयारियों के तहत जी20 की तर्ज पर देश के सभी राज्यों में रीजनल एआई

समिट आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में मेघालय और ओडिशा में ऐसे समिट सफलतापूर्वक हुए और आज राजस्थान में यह रीजनल समिट संपन्न हो रहा है। इस दौरान राजस्थान की एआई पॉलिसी का शुभारंभ किया गया साथ ही युवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक नए स्किलिंग प्रोग्राम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और छोटे उद्यमियों को एआई स्किल्स प्रदान करना है ताकि वे अपनी जिंदगी में, खासकर लघु उद्योगों में, एआई का उपयोग कर प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें और लाभ उठा सकें। इसी क्रम में 10 लाख युवाओं और छोटे उद्यमियों को एआई स्किल्स देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अगले एक साल में हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के तकनीक को सभी तक पहुंचाने के संकल्प के तहत एआई मिशन में 38 हजार एआई जीपीयू यानी एआई कंप्यूटर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इससे देश में बहुत कम कीमत पर सभी को एआई सुविधाएं मिल रही हैं। भारत में एआई क्षेत्र में लगभग 70 बिलियन डॉलर का निवेश हो रहा है,जो एक बहुत बड़ा निवेश है। इस मिशन में कई नए प्रयोग,नए एप्लिकेशन और नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं। वैष्णव ने एआई के आर्किटेक्चर की पांच लेयर्स का जिक्र करते हुए बताया कि सबसे ऊपर एप्लिकेशन लेयर है।

गुजरात-कर्नाटक में 7 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

नई दिल्ली,06 जनवरी 2026। गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मंगलवार को अलग-अलग जगहों पर बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। गुजरात की छह कोर्ट, उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और कर्नाटक के मैसुरु जिला कोर्ट को धमकी दी गई। सभी मामलों में पुलिस और बम स्क्वॉड ने मौके पर जांच की, लेकिन किसी भी कोर्ट या ट्रेन से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं, केरल के कन्नूर जिले में पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों से 12 देसी विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं। सभी मामलों की जांच की जा रही है। गुजरात में हाईकोर्ट और 5 लोकल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली। सूरत की कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल पर सोमवार रात 2 बजे धमकी भरा ईमेल आया था। सुबह जब कर्मचारियों ने ईमेल चेक किया तो पुलिस को सूचना दी। आणंद, राजकोट, अहमदाबाद और भरूच के सेशन कोर्ट को इसी तरह का ईमेल मिला। हालांकि, बम स्क्वॉड की जांच में कोर्ट से कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। पुलिस के अनुसार, यह धमकी एलटीटीई (लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम) के नाम से दी गई है।

कुपोषण के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक राष्ट्रीय आंदोलन बनना चाहिए : पीयूष गोयल

नई दिल्ली,06 जनवरी 2026। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को एक सामूहिक राष्ट्रीय आंदोलन बनाया जाना चाहिए, जिसमें सरकार, कॉरपोरेट, समुदाय और आम नागरिक सभी की भागीदारी हो। उन्होंने कहा कि कुपोषण का उन्मूलन 'विकसित भारत' के निर्माण और देश के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक भविष्य के लिए अनिवार्य है। गोयल ने यह बातें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित पोषण पर सीएसआर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय और सामाजिक प्रभाव को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। कानून के तहत सीएसआर पर शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च अनिवार्य है, लेकिन इसे न्यूनतम सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए,न कि अधिकतम सीमा के रूप में। उन्होंने सीएसआर को बोझ नहीं,बल्कि समाज के लिए सार्थक योगदान का अवसर बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा

कि सेवा की भावना भारत की संस्कृति और परंपराओं में रची-बसी है और कई संस्थान स्वेच्छा से सामाजिक कार्यों पर निर्धारित सीमा से कहीं अधिक खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कार्यक्रम सभी हितधारकों के लिए कुपोषण के खिलाफ प्रयास तेज करने का आह्वान है। पीयूष गोयल ने कहा कि कुपोषण एक जटिल चुनौती है, जिसके समाधान के लिए समन्वित प्रयास जरूरी हैं।

दूषित पानी पर हाईकोर्ट सख्त...कहा- स्वच्छ पेयजल मौलिक अधिकार,सरकार के जवाब को बताया असंवेदनशील

इंदौर,06 जनवरी 2026। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को दूषित पेयजल से जुड़े मामले पर 4 से 5 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस घटना ने इंदौर शहर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब दूषित पानी की वजह से पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इंदौर ही नहीं,बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पानी जनता का मौलिक अधिकार है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो दोषी अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी भी तय की जाएगी। साथ ही संकेत दिए गए कि अगर पीड़ितों को मुआवजा कम मिला है तो उस पर भी अदालत उचित निर्देश जारी करेगी।

मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश

कोर्ट ने दूषित पानी से प्रभावित मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले में हुई मौतों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है। अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी, जिसमें मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

अब तक 17 लोगों की मौत, 421 मरीज अस्पतालों में भर्ती

बताया गया कि दूषित पानी पीने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 110 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि कुल 421 मरीजों को अब तक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनमें से 311 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। आईसीयू में 15 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं उल्टी-दस्त के 38 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 6 मरीजों को अरबिंदो अस्पताल रेफर किया गया है।

प्रशासन शिकायतों पर ध्यान देता तो मौतें नहीं होती

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि 31 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे,लेकिन प्रभावित इलाकों में अब भी दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि प्रशासन ने पहले की गई शिकायतों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया, यदि ऐसा किया जाता तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती।

कर्नाटक में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का सिद्धारमैया ने बनाया रिकॉर्ड

नई दिल्ली,06 जनवरी 2026। आज कर्नाटक की राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सिद्धारमैया ने राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले देवराज अरसू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए 6 जनवरी का दिन ऐतिहासिक है,क्योंकि उन्होंने राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है। सिद्धारमैया अब तक 7 वर्ष और 239 दिन तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने देवराज अरसू के 2,789 दिनों के मुख्यमंत्री कार्यकाल के रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिद्धारमैया अब राजनीतिक हलकों में 'दखले रामैया' के नाम से जाने जाने लगे हैं।

पहली बार 2013 में बने थे मुख्यमंत्री : कांग्रेस पार्टी के सशक्त नेता सिद्धारमैया अपनी राजनीतिक सूझबूझ और जनसमर्थन के बल पर नेतृत्व के शिखर पर पहुंचे हैं। सिद्धारमैया ने पहली बार 2013 में मुख्यमंत्री का पद संभाला और 2013 से 2018 तक पांच साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। अपने पहले कार्यकाल के दौरान सिद्धारमैया ने 1,829 दिनों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बहुमत से जीत के बाद सिद्धारमैया ने 20 मई, 2023 को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

आज उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे लंबे कार्यकाल का देवराज अरसू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस बीच, सिद्धारमैया ने राज्य का बजट पेश करने में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने अब तक कुल 16 बजट पेश किए हैं,जिससे वे कर्नाटक के इतिहास में सबसे अधिक बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सिद्धारमैया के राजनीतिक करियर की शुरुआत लोक दल से हुई। बाद में वे जनता दल में शामिल हो गए और राज्य की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे।

रिकॉर्ड तोड़ने के लिए राजनीति नहीं की : सिद्धारमैया

समाज में आज भी असमानता मौजूद है और जब तक यह समाप्त नहीं होती तथा सभी को समान न्याय नहीं मिलता,तब तक वे संघर्ष करते रहेंगे और जनता के लिए काम करते रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह बात मंगलवार को मैसूरु स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान कही। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अरसू के शासनकाल के रिकॉर्ड की बराबरी करने से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने कभी रिकॉर्ड तोड़ने के उद्देश्य से राजनीति नहीं की। यह रिकॉर्ड संयोगवश बना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें यह जानकारी तक नहीं थी कि देवराज अरसू ने कितने वर्षों तक राज्य का नेतृत्व किया था। यह सब जनता के आशीर्वाद और समर्थन से संभव हो पाया है।

बांग्लादेश में 18 दिन में छठे हिंदू की हत्या

दुकानदार पर धारदार हथियार से हमला

नई दिल्ली,06 जनवरी 2026। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय शरत चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है। यह बीते 18 दिनों में छठे हिंदू व्यक्ति की हत्या है। शरत चक्रवर्ती मणि पलाश उपजिला के चारसिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे। इसी दौरान अचानक पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 19 दिसंबर को मणि ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी और अपने इलाके को मौत की घाटी बताया था। 5 जनवरी को ही जेसोर जिले में भी एक हिंदू व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोनिरामपुर इलाके में एक आइस फैक्ट्री मालिक राणा प्रताप बैरागी की सार्वजनिक रूप से हत्या हुई। वे कपलिया बाजार में आइस फैक्ट्री चलाते थे और दैनिक बीडी खबर अखबार के कार्यकारी संपादक भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक, बाइक पर सवार तीन हमलावर उन्हें फैक्ट्री से बाहर बुलाकर एक गली में ले गए और सिर में नजदीक से गोली मारकर फरार हो गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

संपादकीय

उच्च शिक्षा की समस्याओं का समाधान

अगर हमें 2035 तक सकल नामांकन का अनुपात 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है और केवल डिग्री पर केंद्रित न रह कर सीखने की सामर्थ्य को प्रोत्साहित करना है तो संस्थान निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। हमारे आज के प्रयास से भारत के शिक्षा संस्थान न केवल युवा पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं को सही दिशा दे सकेंगे, बल्कि यही युवा आगे चलकर विकसित भारत 2047 की नींव भी मजबूत करेंगे...

केवल डिग्री हासिल कर लेने को शिक्षा नहीं कह सकते। शिक्षा वह शक्ति है, जो जीवन को दिशा देती है। सफल शिक्षा एक व्यक्ति के सोचने का तरीका बदल सकती है,उसे जीवन उद्देश्य दे सकती है और अपने भीतर छिपी संभावनाएं पहचानने का अवसर दे सकती है। खासतौर पर उच्च शिक्षा वह पड़ाव है, जहां युवा अपनी रुचियों और क्षमताओं को पहचानते हैं और भविष्य की राह खोजने की शुरुआत करते हैं। जहां एक तरफ स्कूली शिक्षा हमें हमारे आसपास की दुनिया का ज्ञान देती है,वहीं उच्च शिक्षा छात्रों को अपने विकल्प जानने की आजादी देती है। उच्च शिक्षा समय है अलग-अलग विषयों और क्षेत्रों को समझने और यह तय करने का कि उन्हें जीवन में क्या करना है। यह प्रक्रिया सरल नहीं, जटिल होती है। एक छात्र के आजादी से अपनी राह चुन सकने के पीछे एक मजबूत संस्थान,संसाधन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।

भारत जैसे विशाल और विविध देश में संस्थान निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है। हर साल लाखों छात्र स्कूलों से निकलकर उच्च शिक्षा की ओर रुख करते हैं, लेकिन संस्थानों में इतनी सीटें ही नहीं कि सबको दाखिला मिल सके। नतीजतन प्रतिस्पर्धा और तेज होती जा रही है और परीक्षाएं और ज्यादा मानकीकृत हो रही हैं। इस सबके साथ-साथ व्यवस्था अक्सर प्रशासनिक सुविधा की सहूलियत देखती है। इस गहन माहौल में हर छात्र की अलग पहचान और क्षमता पर ध्यान दे पाना असंभव हो जाता है। आज भारत में लगभग 70,018 उच्च शिक्षा संस्थान हैं।

भले ही यह उत्साहजनक लगे,लेकिन देश की जरूरतों के मुकाबले अभी भी पर्याप्त नहीं। युवावर्ग अब भी बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा खोज रहा है। आपूर्ति की कमी का असर छात्र के इस निर्णय पर पड़ता है कि वह कहां पढ़े। सख्त आव्रजन नीतियों के बाद भी भारतीय छात्र बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने जा रहे हैं। कनाडा,अमेरिका और ब्रिटेन उनके प्रमुख गंतव्य हैं। हालांकि अब फ्रांस,आयरलैंड और इटली भी तेजी से छात्रों में लोकप्रिय हो रहे हैं। जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 12 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे थे। इस आंकड़े से घरेलू स्तर पर आवश्यकता और सीमित विकल्प साफ उजागर होते हैं। इन चुनौतियों के बीच से ही बड़े अवसर भी उत्पन्न होते हैं।

तेजी से बदलती दुनिया में पहला अवसर नवाचार में निहित है। भारत में हमें अधिक बहुविषयक कार्यक्रमों की आवश्यकता है। हमें ऐसे कार्यक्रमों के बारे में सोचना होगा,जो तकनीक,पर्यावरण,सूचना और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हों। मैनेजमेंट, कानून और मेडिकल जैसे पारंपरिक कोर्स को भी नए ढंग से देखना होगा। नए पाठ्यक्रम,बेहतर तकनीक और उद्योग से पढ़ाई को जोड़ कर भारतीय संस्थान खुद को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना सकते हैं। दूसरा बड़ा अवसर है, डिजिटल शिक्षा। हाइब्रिड माडल प्रभावी हो सकते हैं,जिन्हें आनलाइन और आफलाइन पढ़ाई को मिलाकर बनाया गया हो। अगर सही ढंग से लागू किए जाएं तो ये बड़े पैमाने पर लाभकारी शिक्षा का साधन बन सकते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश में,जहां छात्र दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, डिजिटल शिक्षा एक असरदार समाधान प्रस्तुत करती है।

अपने सशक्त डिजिटल ढांचे की सहायता से भारत विश्व के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है, और उसे ऐसा करना भी चाहिए। नीतिगत स्तर पर आज सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं। तीन दशक बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों का बीड़ा उठाया है। बहुविषयक पढ़ाई,विषयों में लचीलापन और संस्थानों की स्वायत्तता जैसे विचारों पर अब जोर दिया जा रहा है। दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र के पूर्व अनुभव बताते हैं कि जब-जब सरकारें शोध, नवाचार और तकनीक को शिक्षा का केंद्र बनाती हैं,तब-तब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है। तीसरा अहम पहलू है, प्रतिभा निर्माण। उच्च शिक्षा संस्थान का उद्देश्य केवल रुखा ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों के सोच के दायरे को विस्तार देना,कौशल को बढ़ाना और छात्रों को पेशेवर समझ देना भी है। सार्थक शिक्षा देश को ऐसा मानव संसाधन देती है, जो न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने क्षमता रखता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी आत्मविश्वास के साथ अपना योगदान दे सकता है।

अगर हम पीछे मुड़ कर देखेंगे तो पाएंगे कि उच्च शिक्षा की परंपरा हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। अपने-अपने समय में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्र विश्व भर से विद्वानों को आकर्षित करते रहे। इन सभी ने जिज्ञासा एवं शोध को शिक्षा का मूल सिद्धांत बनाया। आज भले ही समय और परिस्थितियां बदल गई हों,लेकिन हमारा लक्ष्य और भी स्पष्ट है। अगर हमें 2035 तक सकल नामांकन का अनुपात 50 प्रतिशत तक पहुंचाना है,उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है और केवल डिग्री पर केंद्रित न रह कर सीखने की सामर्थ्य को प्रोत्साहित करना है तो संस्थान निर्माण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। हमारे आज के प्रयास से भारत के शिक्षा संस्थान न केवल युवा पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं को सही दिशा दे सकेंगे,बल्कि यही युवा आगे चलकर विकसित भारत 2047 की नींव भी मजबूत करेंगे।

सिक्योरिटी काउंसिल की अवहेलना करते ट्रंप हुए बेनकाब

अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है! इसकी संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है! विश्व में फिर युद्ध कभी ना हो इस बात को लेकर अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की थी ! वैसे तो इसके कई अंग है लेकिन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल इसके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है!

प्रोफेसर शाम लाल कौशल
रोहतक--124001(हरियाणा)

अगर कोई संकटकालीन स्थिति पैदा हो जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाती है जिसके 15 सदस्य हैं जिनमें अमेरिका,इंग्लैंड, फ्रांस,रूस तथा चीन स्थाई सदस्य हैं और 10 और सदस्य हैं जिन्हें दो-दो साल के लिए चुना जाता है। जो देश सिक्योरिटी काउंसिल के स्थाई सदस्य हैं उन्हें वीटो पावर मिली हुई है, इसका मतलब यह है की जो फैसला होता है वीटो पावर के द्वारा उसे रद्द किया जा सकता है। जनरल असेंबली में इस समय 193 देश हैं जो समय-समय पर विभिन्न वैश्विक समस्याओं पर विचार विमर्श करते रहते हैं! संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार कोई भी देश किसी दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता,मतभेद होने की स्थिति में आपस में बातचीत करके समाधान ढूंढा जा सकता है!लेकिन काफी समय से यह देखा जा रहा है के विभिन्न देश संयुक्त राष्ट्र की अवहेलना करके आपसी मतभेदों को लेकर एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं जिससे युद्ध का खतरा बना रहता है! इस समय विश्व में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं! संयुक्त राष्ट्र की स्थापना करने वाला अमेरिका खुद ही इसकी अवहेलना करता है! सिक्योरिटी काउंसिल की अवहेलना करके अमेरिका ने पहले इराक पर हमला करके उसके राष्ट्रपति, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया और बाद में उसको फांसी की सजा दे दी गई, उसके बाद अमेरिका ने नाटो देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया! इसराइल तथा ईरान में युद्ध में भी यह इजरायल की मदद करता रहा है! रूस यूक्रेन युद्ध में इसकी अहम भूमिका रही है! अमेरिका समय-समय पर कई देशों में सत्ता परिवर्तन करवा चुका है! अभी इसने मादक पदार्थों की अमेरिका में तस्करी रोकने के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति,मादुरो तथा उसकी पत्नी को उनके बेडरूम से उठा लिया और अमेरिका में उन्हें अदालत में नारको एक्ट के तहत मुकदमे के लिए पेश किया गया। अमेरिका के दूसरी बार बने राष्ट्रपति,डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाने के बाद, ट्रंप ने 10 और देशों पर कब्जा करने का ऐलान किया है जो कि अमेरिका के लिए सिरदर्दी बने हुए हैं। इसमें ईरान सबसे ऊपर है। ईरान पर पहले ही कई प्रतिबंध लगे हुए हैं क्योंकि वह यूरेनियम का प्रयोग बम बनाने के लिए कर रहा है। ईरान में इस्लामी सरकार है। ईरान के लोग महंगाई तथा बेरोजगारी को लेकर सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 14 लोग मारे भी गए हैं। हो सकता है कि ईरान में आंतरिक गड़बड़ी के लिए अमेरिका तथा इजरायल काम कर रहे हो। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर

प्रशासन ने ईरान के प्रदर्शनकारी लोगों पर और अत्याचार किये तो का हस्तक्षेप करेगा। इस धमकी से ईरान में काफी खौफ है। हो सकता है कि ईरान में तख्ता पलट भी हो जाए। अमेरिका के निशाने पर डेनमार्क,ग्रीनलैंड,ईरान, कोलंबिया,मेक्सिको,उत्तरी कोरिया, चीन तथा रूस आदि देश है जो कि अमेरिका की आंख की किरकिरी है। वेनेजुएला पर आक्रमण करने का अमेरिका का मुख्य उद्देश्य इस देश के विश्व के सबसे ज्यादा तेल भंडारों पर कब्जा करना है। अन्य देशों पर भी कब्जा करने का मकसद वहां के खनिज पदार्थों पर कब्जा करना है। वेनेजुएला पर आक्रमण करके वहां के राष्ट्रपति मादुरो तथा उनकी पत्नी को उठाकर कर ले जाना तथा उन पर नारको एक्ट के तहत मुकदमा चलाना विश्व के अन्य देशों के लिए एक चेतावनी है। जो देश भी अमेरिका के मुताबिक नहीं चलेगा उसे देश के राष्ट्रपति को इसी तरह उठा लिया जाएगा। रूस,चीन तथा विश्व के अनेक देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की इस तानाशाही का विरोध किया है। यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की अवहेलना है। अमेरिका की नकल करते हुए अगर चीन ताइवान के ऊपर कब्जा कर ले तो किसी को क्या एतराज हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में आजकल जो सैनिक टकराव चल रहा है उसमें अगर पाकिस्तान अफगा निस्तान के शासको को उठाकर पाकिस्तान ले आए तो अमेरिका की तरह उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वेनेजुएला पर ट्रंप के द्वारा कार्रवाई करके ट्रंप ने विश्व के कई नेताओं को चेतावनी दे दी है। असल में तो ट्रंप ने वर्ल्ड ऑर्डर को ठेंगा दिखा दिया है। कल को कोई भी देश अमेरिका की तरह दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर सकता है। ट्रंप समय-समय पर विभिन्न देशों में चल रहे युद्धों को रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद करता रहा है। लेकिन वेनेजुएला प्रश्न कार्रवाई करके वह बेनकाब हो गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाने के बाद वहां पर फैल्सी रॉड्रिग्स को कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया गया है जिसने अमेरिका की भर्त्सना की है और अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की है। इसी बात से उत्साहित होकर यूक्रेन के राष्ट्रपति, जैलेंस्की ने रूस के खिलाफ भी वेनेजुएला की तर्ज पर कार्रवाई करने की बात कही है। क्योंकि भारत ने अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका की आलोचना की है इसीलिए ट्रंप ने एक बयान में कहा है के भारत के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा,100 प्रतिशत टैरिफ लगाना पड़ेगा! अमेरिका द्वारा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को इस तरह धमकी देना मर्यादा की अवहेलना है। भारत को स्पष्ट तौर पर अमेरिका की निंदा करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी अमेरिका पहले ही पाकिस्तान के पक्ष में स्टैंड ले चुका है। भारत को चाहिए कि वह ब्रिक्स तथा शंघाई संगठन के साथ जुड़कर अमेरिका के साथ मुकाबला करें। भारत एक संप्रभु देश है! हम राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर रूस या किसी अन्य देश के साथ व्यापार करें, अमेरिका कौन होता है हमें हुकुम देने वाला! भारत अमेरिका की कोई रियासत नहीं! भारत एक शक्तिशाली बाजार वाला देश है! अमेरिका द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बावजूद भी अमेरिका में निर्यात कम नहीं हुए! बल्कि अमेरिका को ही नुकसान हुआ है! लेकिन ट्रंप? जिद्दी हैं! बेशक अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील चल रही है,उसी को लेकर भारत ने रूस से तेल मंगवाना कम कर दिया है और अमेरिका की किसी कार्रवाई के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं करता। अमेरिका चाहता है कि उसके कृषि पदार्थों को भारत के बाजारों में बेचने की अनुमति दी जाए। अगर भारत ऐसा मान लेता है तो भारतीय कृषकों को भारी नुकसान होगा। इसलिए भारत अमेरिका की यह शर्त मानने को तैयार नहीं जिसको लेकर अमेरिका भारत से टैरिफ कम नहीं करेगा। भारत को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। अगर रूस,चीन,उत्तरी कोरिया तथा ईरान आपस में मिल जाते हैं तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सैनिक चुनौती पैदा कर सकते हैं। अमेरिका को दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप करना बंद करना पड़ेगा। ट्रंप तो मेक्सिको को अमेरिका का भाग बनाने की बात पहले ही कह चुके हैं। वेनेजुएला पर कार्रवाई ने उनका पर्दाफाश कर दिया है। टैरिफ की नीति के द्वारा भी ट्रंप ने दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ रिश्ते बिगाड़ दिए हैं। ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं समझते। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर यूरोपीय देश ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। अगर ट्रंप ने अपनी महत्वाकांक्षा पर रोक नहीं लगाई तो कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है।

निरंतर श्रम,संयम और संकल्प लक्ष्य प्राप्ति के सच्चे और मौन साधक

संजीव ठाकुर,
रायपुर छत्तीसगढ़,

जिंदगी का मूल ही निरंतर संघर्ष श्रम संकल्प और प्रगति है। सकारात्मक उद्देश्य को लेकर किया गया श्रम सदैव श्रेष्ठ परिणाम देता है। श्रम और संघर्ष का कोई विकल्प ही नहीं है। निरंतर श्रम करना उच्च मनोबल बनाए रखना और सफलता की कामना और पवित्र महत्वाकांक्षा सफल मनुष्य के सच्चे मित्र होते हैं। जीवन है चलने का नाम,गति का नाम ही जीवन है। सभी समाज एवं राष्ट्र की संस्कृतियों ने यह माना है कि मनुष्य और जानवरों के बीच विभेद करने वाला प्रमुख कारक मस्तिष्क है, और मस्तिष्क ही मनुष्य को सृजनात्मक शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के रचनात्मक विचार नयापन लाते हैं उसे पूर्व काल से पृथक करते हुए प्रगति के पथ प्रदर्शक बनते हैं। इसे ही नवप्रवर्तन माना जाता है। नवप्रवर्तन और कुछ नहीं बल्कि समाज की परंपरागत और प्रगतिशील मानसिकता के बीच एक बड़ी लाइन खींचना है। इसीलिए यह माना जाता है कि नवप्रवर्तन समाज में 3 प्रतिशत नवाचार का निर्धारित है, शेष 97 प्रतिशत परंपरावादी विचारों के लिए है। पुराने समय से ही आर्थिक समृद्धि में नवप्रवर्तन की भूमिका को स्वीकार किया गया है चाहे वह मनुष्य के खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक में परिवर्तन हो या फिर 18वीं सदी में यूरोप की वाणिज्य क्रांति का औद्योगिक क्रांति में बदलना इन सभी में नवप्रवर्तन ने प्रेरक का काम किया है। हम चौथी क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि विचारों को कभी सुसुप्त होने या मरने ना दिया जाए। हो सकता है आपके

विचार करोड़ों डॉलर के हो । वर्तमान अर्थव्यवस्था में समृद्धि के इंजन माने जाने वाले सनराइज उद्योग,सॉफ्टवेयर, खाद्य संस्करण,इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक के विकास के पीछे भी नवप्रवर्तन का हाथ है। इसी के आधार पर नगरों को स्मार्ट नगरों में बदला जा रहा है। नवप्रवर्तन या नवाचार से मैं सिर्फ मानव जीवन की परेशानियों को न्यूनतम किया है,बल्कि मानव जीवन को आसान और सुखमय भी बनाया जा रहा है। नवप्रवर्तन और मस्तिष्क की खोज के कारण ही जापान में 6.5 रेक्टर का भूकंप सामान्य माना जाता है,जबकि भारत में यह तबाही ला सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक (एंटीबायोटिक) के अविष्कार ने रोगों की संभावना को कम कर दिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली के भावी विकास को एक गति प्रदान की है। जेनेरिक औषधि, रोबोटिक सर्जरी,जीन एडिटिंग जैसी प्रक्रिया स्वास्थ्य सुधार हेतु एक मजबूत आधार मानी जाती है। सामाजिक विकास आर्थिक समन्वयक और न्याय प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास नवप्रवर्तन के योगदान से ही आया है। सोशल मीडिया जैसे नवीन प्लेटफार्म ने व्यक्ति की अभिव्यक्ति के अधिकार को स्वतंत्र किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रामीण से आधुनिक रूपांतरण में कृषी क्षेत्र से भारी उद्योगों पर बल देने में किसानों के देश को सॉफ्टवेयर उद्योग का सिरमौर बनाने में नवप्रवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय कृषि में भी आधुनिकीकरण और पाश्चात्य उपकरण का प्रादुर्भाव भी नवीन नवाचार के कारण संभव हुआ है। भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य से लोगों के सशक्तिकरण करने वाले राज्य में बदलने की नवप्रवर्तन की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। इसके कारण भार मानी जाने वाली महिलाएं अब भार ढोने वाली की भूमिका में आ चुकी हैं। इसी तरह न्यायिक क्षेत्र में जनहित याचिका की अवधारणा ने न्याय की अवधारणा को सर्वांगीण बनाने में सहायता प्रदान की है। यह अलग बात है कि केवल नवप्रवर्तन को ही एकमात्र निर्धारक कारक के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि नवीन विचारों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना बहुत हद तक समाज पर निर्भर करता है। पश्चिमी देशों में नवीन विचारों को जगह देने के कारण वहां पुनर्जागरण आया है। हमें समाज को नव परिवर्तन की तरफ जागरूक करने की आवश्यकता होगी और नवप्रवर्तन में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देकर उस और और ज्यादा विचार-विमर्श कर नीति बनाने की आवश्यकता होगी। इस तरह हमें महात्मा बुद्ध के कथन अनुसार अपने या दूसरों के विचारों नवप्रवर्तनों को तर्क बुद्धि पर देखे जाने की जरूरत है, और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाना चाहिए।

कविता

असली चेहरा सामने आया...!

संजय एम. तराणेकर,
इन्दौर-452011
(मध्यप्रदेश)

ट्रम्प का असली चेहरा सबके सामने हैं आया,
व्यापार के नाम पे उसने सबको है धमकाया।
शांति का नोबेल पुरस्कार हासिल न हो पाया,
विश्व शांति के नाम खलनायक बनकर आया।
वेनेजुएला राष्ट्रपति मादुरो की पत्नी सिलिया,
अंतरराष्ट्रीय कानूनों को धता करके लील गया।
यह दृश्य देख के इतिहास ने खुद को दोहराया,
हथियारों के नाम पर सद्दाम को फाँसी चे ाया।
सारी दुनिया का ठेका अमेरिका को मिल चुका,
संप्रभु देश पर आक्रमण से सबका सिर झुका।
अब तो अमेरिका खुद कटघरे में खड़ा हुआ है,
देखिए यूं सत्य का मस्तक कैसे झुका हुआ हैं।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

यूनुस की भूमिका ही संदेहास्पद

गुलाबी जगत

भारत ने बांग्लादेश को 2024 और 2025 में 120-120 करोड़ रुपए के पैकेज दो बार दिए। 'लाइन ऑफ क्रेडिट' में 25 फीसदी कर्ज ब्याज की बेहद आसान दरों पर दिया। भारत बांग्लादेश को 60 फीसदी प्याज, 78 फीसदी मसालों, 65 फीसदी चावल,19 फीसदी रासायनिक उत्पादों और करीब 20 फीसदी बिजली की आपूर्तियां करता है। ढाका का कपड़ा उद्योग भारत की कृपा पर ही चलता है। बांग्लादेश में मेडिकल वीसा की मांग सबसे अधिक भारत के लिए है। वहां के लोगों के अनुभव हैं कि भारत में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हैं। यदि भारत मौजूदा हालात के मद्देनजर इन आपूर्तियों को रोक दे, तो क्या बांग्लादेश जिंदा रह सकता है? क्या बांग्लादेश में खाद्य संकट पैदा नहीं होगा और वह अंधेरे में डूब नहीं जाएगा? बांग्लादेश के साथ भारत नदियों का पानी और अन्य संसाधन भी साझा करता रहा है। दिसंबर, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 फौजियों का आत्मसमर्पण एक अर्द्धसत्य है। बांग्लादेश की मुक्ति और आजादी की उस लड़ाई में भारत को भी अपने 3864 जांबाज सैनिकों और अफसरों की शहादतें देनी पड़ी थीं। उस दौर में करीब 10 लाख बहन-बेटियों-माताओं के साथ बलात्कार किए गए थे। हत्याओं का कोई निश्चित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार (परोक्ष रूप में प्रधानमंत्री) मुहम्मद यूनुस का एक कुरूप यथार्थ सामने

आया है कि उन्होंने 2016 में 3 लाख डॉलर (करीब 2.5 करोड़ रुपए) 'हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन' को दान दिए थे। यूनुस को अमरीका की कृपा से ही नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। उनके 'गरीब,ग्रामीण बैंक' की दुनिया में खूब चर्चा हुई थी, लेकिन बाद में सच बेनकाब हुए कि गरीब, मछुआरों,किसानों का पैसा लूट कर किसको चढ़ावा दिया जा रहा था? यूनुस को जेल भी जाना पड़ा। तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी भी यूनुस को झेलनी पड़ी थी। ट्रंप आज भी अमरीकी राष्ट्रपति हैं, लिहाजा हिलेरी-यूनुस की कथित भ्रष्ट मिलीभगत,सांठगांठ और लेन-देन की जांच कराई जा रही है। यूनुस अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में बांग्लादेश में गद्दीनशीं किए गए।

बाइडेन भी क्लिंटन की डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति थे। बहरहाल आज क्लिंटन परिवार अमरीकी राजनीति और प्रशासन में अप्रासंगिक है, लिहाजा अमरीका के स्तर पर आज कोई भी यूनुस का पैरोकार नहीं है। यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार 8 अगस्त, 2024 से जारी है, जबकि बांग्लादेश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। न जाने क्यों बांग्लादेश में किसी भी बौद्धिक और राष्ट्रवादी नागरिक ने इस व्यवस्था को अदालत में चुनौती नहीं दी है? संविधान में सिर्फ यह व्यवस्था है कि कार्यवाहक सरकार को तीन महीने की अवधि में चुनाव निश्चित रूप से कराने हैं,ताकि एक जनादेशी और लोकतांत्रिक सरकार देश का नेतृत्व संभाल सके। आज बांग्लादेश में अराजकता,हिंसा, सांप्रदायिकता,हत्याओं का दौर है, तो यूनुस ही उसके लिए 'खलनायक' हैं,क्योंकि वह कट्टरपंथी जमात को उकसा रहे हैं। सजायाफ्ता आतंकियों को जेल से रिहा कराया है। सड़कों पर भारत-विरोधी, हिंदू-विरोधी जो भीड़ नजर आ रही है,यूनुस उसे नियंत्रित ही नहीं करना चाहते। वह चुनाव को आगे खिसकाने के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। यूनुस ने अपने कार्यकाल में, खासकर 1.30 करोड़ अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए, ऐसे अराजक और हत्यारे हालात बना दिए हैं कि हिंदू खौफ और दहशत में जीने को अभिशप्त हैं। जिस निर्ममता, बर्बरता के साथ हिंदुओं की हत्याएं की गई हैं, भारत के विरोध में हमलावर दुष्प्रचार जारी है,उसके मद्देनजर भारत सरकार को बांग्लादेश की आपूर्तियों में तुरंत कटौती करनी चाहिए और अंतरिम सरकार को निर्णायक चेतावनी जारी करनी चाहिए। देश की मोदी सरकार को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में इंसाफ और इनसान दोनों ही जल रहे हैं। यूनुस एक साल में दो बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं।

सुशासन,संवेदना और सुरक्षा: श्रमिक हित में छत्तीसगढ़ सरकार के दो वर्ष

छगनलाल लोन्हारे

सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की संकल्पबद्ध प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन का श्रम विभाग विगत दो वर्षों में इसी सुशासन की भावना को धरातल पर साकार करता हुआ दिखाई देता है। इस अवधि में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, उनके जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने तथा उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए अनेक ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम उठाए गए हैं।

विष्णु के सुशासन की स्पष्ट झलक श्रम विभाग द्वारा अपनाए गए डिजिटल नवाचारों में दिखाई देती है। प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से समस्त नस्तियों का संधारण ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। विभागीय योजनाओं और सेवाओं को आमजन के लिए सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने हेतु एक आधुनिक, यूज़र-फ्रेंडली विभागीय वेबसाइट विकसित की गई है। श्रमिकों की सुविधा को केंद्र में रखते हुए तैयार किया गया 'श्रमेव जयते' मोबाइल ऐप श्रमिक पंजीयन, योजनाओं में आवेदन तथा श्रमिक पलायन की ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है, जो डिजिटल सुशासन की दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

राज्य के नवगठित जिलों तक श्रम विभाग की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पाँच नवीन श्रम पदाधिकारी कार्यालयों की स्थापना हेतु 20 पदों का सृजन किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 के दौरान श्रमायुक्त संगठन अंतर्गत श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के पदों पर कुल 32 नई नियुक्तियाँ की गईं। इन

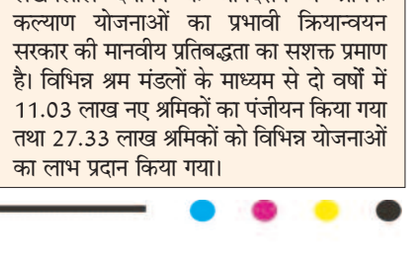

प्रयासों से न केवल विभागीय कार्यों में गति आई, बल्कि श्रमिकों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ भी सुनिश्चित हुईं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में आवश्यक और संतुलित सुधार करते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और श्रमिक हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित किया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम,2017 के प्रभावी क्रियान्वयन से छोटे व्यापारियों को राहत मिली, वहीं नियत कालिक नियोजन कर्मकार की नई श्रेणी ने रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोले।

राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत लागू किए गए छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन एवं विविध प्रावधान विधेयक,2025 के माध्यम से अवैधानिक हड़ताल पर नियंत्रण, छोटे अपराधों में समझौते तथा लघु उद्योगों को छूट जैसे प्रावधान किए गए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में रात्रि पाली में महिला कर्मकारों के सशर्त नियोजन की अनुमति देना सरकार की प्रगतिशील और संवेदनशील सोच को दर्शाता है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में श्रमिक कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की मानवीय प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। विभिन्न श्रम मंडलों के माध्यम से दो वर्षों में 11.03 लाख नए श्रमिकों का पंजीयन किया गया तथा 27.33 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

CMYK

शीतलहर के कारण छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बलरामपुर जिलों में स्कूलों की छुट्टी और समय में बदलाव.....

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

सरगुजा और बलरामपुर जिलों में पिछले दो दिनों से जारी शीतलहर ने ठंड की स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया है। इस कारण बच्चों और अन्य नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चों को स्कूल जाते समय कड़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा था। इस पर ध्यान देते हुए, जिला प्रशासन ने बच्चों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरगुजा जिले में, कलेक्टर अजीत वसंत ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी है। यह फैसला शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए लिया गया है। साथ ही,सरगुजा जिले में दो पालियों में संचालित होने वाले विद्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। अब, प्रथम पाली की कक्षाएं सुबह 9.30 बजे से 12.30 बजे तक और दूसरी पाली की कक्षाएं 12.30 बजे से 4 बजे तक संचालित होंगी। यह आदेश जिले के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिए लागू होगा। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि 10 जनवरी के बाद, स्कूलों का समय पूर्व निर्धारित रूप में जारी रहेगा और 31 जनवरी तक वही समय सारणी लागू होगी। इसके तहत पहली पाली का समय सोमवार से शुक्रवार तक 9.30 बजे से 12.30 बजे तक और शनिवार को 12.30 बजे से 4 बजे तक रहेगा। दूसरी पाली में कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार तक 12.30 बजे से 4 बजे तक चलेंगी और शनिवार को सुबह 9.30 बजे से 12.30 बजे तक। प्रथम पाली में चलने वाले विद्यालयों का समय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा और शनिवार को यह समय 9.30 बजे से 12.30 बजे तक होगा। इसके अतिरिक्त,सभी शैक्षणिक और अन्य कर्मचारियों को भी समय पर स्कूल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि,ठंड से बचाव के लिए उन्हें आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है।

बलरामपुर जिले में भी छुट्टियां बढ़ाई गईं

बलरामपुर जिले में भी बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए छुट्टियां घोषित की गईं। पहले 6 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई थी, लेकिन तापमान में और गिरावट आने और शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए छुट्टी बढ़ा दी गई है। अब, बलरामपुर जिले में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 8 जनवरी तक स्कूल से छुट्टी रहेगी। इससे पहले, बलरामपुर कलेक्टर ने 6 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा की थी,लेकिन ठंड में और वृद्धि होने के कारण उन्होंने इसे दो दिन और बढ़ा दिया है।

ठंड में गिरावट का असर

मौसम में लगातार गिरावट के कारण पूरे जिले में ठंड में वृद्धि हो रही है। न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक दर्ज किया गया है,जो कि 24 घंटों में 3 डिग्री की गिरावट दर्शाता है। पाट क्षेत्रों में तापमान और अधिक गिर चुका है और वहां का पारा 2 डिग्री के पास पहुंच चुका है। मैनपाट और सामारी पाट जैसे इलाकों में ओस की बूंदें जमने लगी हैं, जो ठंड का और अधिक अहसास कराते हैं।

शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। उत्तर दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं के कारण ठंड में और वृद्धि होने की संभावना है,जिससे फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और शीतलहर से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों की सलाह दी है।

मवेशी चोरी के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार 3 पिकअप व आधा दर्जन मवेशी जब्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

मवेशी चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी शहर में घुम-घुमकर चार पहिया वाहन से मवेशी चोरी कर झारखंड लेजाकर बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से आधा दर्जन मवेशी व तीन पिकअप वाहन सहित रुपए जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

जानकारी के अनुसार घुटरापारा निवासी ऋषिकेश मिश्रा 4 जनवरी की रात 11.30 बजे अपने दोस्त के घर से गंगापुर होते हुए रिंग रोड से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि तीन पिकअप वाहनों में 6-7 लोग मवेशियों को पकडक़र जबरदस्ती लोड कर रहे थे। मवेशी जोर-जोर से चिल्ला रहे थे, जिससे प्रार्थी को शक हुआ और उन्होंने वाहनों का नंबर नोट किया। दो पिकअप वाहनों के नंबर नोट करने के बाद वह आरोपियों का पीछा करने लगे, लेकिन वे तेजी से फरार हो गए। इसके बाद प्रार्थी ने पुलिस को सूचना दी और थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और मुखबिर से सूचना मिलने पर तीन पिकअप वाहन रनपुरखुर्द पानी टंकी के पास संदिग्ध स्थान पर खड़े मिले, जिसमें 6 मवेशी लोड किए गए थे। पुलिस ने मौके से आरोपियों को गिरफ्तार किया और मवेशियों को गौ सेवा मण्डल सरगुजा के सुपुर्द किया। गिरफ्तार आरोपियों में अजहर खान,शोएब शाह,जुनैद आलम,अफसार,तकिर खान,आदम शाह और रेफाज खान शामिल हैं,जो सभी जशपुर जिले के निवासी हैं। इन आरोपियों ने मवेशी चोरी की घटना को स्वीकार किया और बताया कि उन्होंने इन मवेशियों को झारखंड के मवेशी बाजार में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों से 12,750 रुपये की राशि भी जब्त की, जो मवेशी बिक्री से प्राप्त हुई थी। आरोपी आदतन है। पूर्व में भी मवेशी चोरी के मामले में गांधीनगर थाने से गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने दरिमा में मतदाता पुनर्निक्षण की ली जानकारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

नव वर्ष के अवसर पर सरगुजा जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव की उपस्थिति में संगठन सृजन कार्यक्रम के तारतम्य में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दरिमा की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस संगठन के अलावा विशेष मतदाता पुनर्निक्षण,धान खरीदी और अन्य ग्रामीणों से जुड़ी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा हुई।

ग्रामीणों ने बताया कि जो गांव शहरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन ग्रामों में ही ज्यादातर नाम काटे गए हैं जबकि मध्य के ग्रामीण बहुल्य गांव में बहुत कम नाम कटे हैं। ग्रामीण इलाके में नोटिस का सिलसिला भी शुरू हो गया है सिंहदेव ने एसआईआर के पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्दबाजी में किए जा रहे हैं इस अभियान में वैध औरअवैध मतदाता निर्धारण में बहुत सारी त्रुटियां पाई जा रही हैं यदि पर्याप्त समय मिलता तो बेहतर ढंग से एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न होती। उन्हें उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि

पूरी प्रक्रिया पर गंभीरतपूर्वक नजर रखें और वास्तविक मतदाताओं का नाम अधिक से अधिक संख्या में सक्रिय होकर जुड़वाने में मदद करें। बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि महात्मा गांधी के पंचायती राज का सपना चकनाचूर किया जा रहा है और पंचायत में शासन स्तर से किसी प्रकार की भी राशि नहीं पहुंच पा रही है, आज तक पंचायत को 15वां वित राशि भी प्राप्त नहीं हुई है।इस कारण से गांव के विकास और उत्थान के सारे कार्यक्रम ठप पड़े हुए हैं। उक्त बैठक में ग्रामीणों ने वर्षों पुरानी दरिमा को नवीन राजस्व ब्लॉक बनाने की मांग दोहराई। ग्रामीणों का कहना है कि दरिमा में तहसील कार्यालय, महिला बाल विकास विभाग का परियोजना कार्यालय, बिजली विभाग आदि अधिकांश कार्यालय स्थापित हो चुके हैं फिर राजस्व विकास खंड क्यों नहीं बनाया जा रहा है। इस मांग के संबंध में पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी पहले सहमति जताई थी। पूर्व उपाध्यक्ष ने ग्रामीणों से कहा कि नवीन राजस्व विकासखंड बनाने के लिए रायपुर से लेकर दिल्ली तक जो भी कोशिश की जानी है उसके लिए मैं भी पूरी मदद देने को तैयार हूं ग्रामीण इस अभियान को आगे बढ़ाएं। श्री सिंहदेव ने कंवर समाज के प्रतिनिधियों तथा उनके परिजनों के साथ 25 वर्षों तक लोकसभा के सांसद रहे स्वर्गीय बाबूनाथ सिंह के अंतिम क्रियाकर्म स्थल का दौरा किया और उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इस स्थान एक शानदार स्मारक बनाया जाए। उसे बनाने में जो भी मदद की आवश्यकता होगी उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। सिंह देव ग्रामीणों केआमंत्रण पर कुनियाकला में चल रहे रामायण पाठ कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष सरगुजा राकेश गुप्ता,विनय शर्मा,विजय सिंह, अनीमा केरकेट्टा, रामसाय,पारस राजवाड़े, नारद गुप्ता,सरिता महंत, परमेन्द्र सरजाल, उत्तम राजवाड़े, संजीव कश्यप,विनोद राजवाडे, उमाशंकर, अरुण गुप्ता,राज कश्यप, कमल, कन्नीलाल,विकास सिंह,नरेन्द्र गुप्ता, गणेश यादव,रवि बड़ा,दीक्षित शर्मा,हुसकुमार सिंह,रविशंकर,वायुश्री सिंह,भोलू गुप्ता,राकेश सोनी समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामवासी मौजूद रहे।

स्कूल में ताला तोड़ के चोरी करने वाले फरार आदतन शातिर चोर हुआ गिरफ्तार,पुलिस ने कार्यवाही कर भेजा न्यायिक रिमांड पर

-संवाददाता-
रघुनाथपुर,06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के थाना रघुनाथनगर पुलिस के द्वारा आदतन व शातिर चोर को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे,चोरी की गई सामग्री भी किया गया बरामद। जानकारी के अनुसार दिनांक 05/01/2026 को प्रार्थी श्री गंभीर सिंह, शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवगवई के द्वारा थाना रघुनाथनगर उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02,04/01/2026 को अज्ञात चोर के द्वारा स्कूल का ताला तोड़कर कंप्यूटर,टैबलेट, बायोमेट्रिक डिवाइस,प्रिंटर मशीन, डीजे साउंड बॉक्स,कुकर,साइंस किट और चावल एवं अन्य सामग्री कुल जुमला रकम करीब 64000 की चोरी अज्ञात चोर कर लिया है। पुलिस ने प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना रघुनाथनगर में अपराध क्रमांक 03/2026 धारा 305ई 331(2) बीएनएस कायम कर

विवेचना लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभव बैंकर के कुशल मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्व दीपक त्रिपाठी व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर श्री राम अवतार ध्रुव के निर्देशन में पुलिस टीम बनाकर अज्ञात चोर की पताशाजी की गई प्रकरण के आरोपी की पताशाजी के दौरान सूत्रों से ज्ञात हुआ कि थाना रघुनाथ नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सरना के प्रमोद साहू पिता कैलाश साहू उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम सरना को घटना दिनांक को चावल बोरा को ले जाते देखा गया था की सूचना पर संदेही को हिरासत लेकर पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार करते हुए (1) पूर्व माध्यमिक शाला नवगवई से कंप्यूटर,टैबलेट,प्रिंटर मशीन, साउंड बॉक्स, कुकर, साइंस किट, चावल 3 क्विंटल वह अन्य सामान कुल रकम 64000 तथा (2) प्राथमिक शाला गैना से सीपीयू, कंप्यूटर सेट, टेबल,एक नग जुमला रकम 27000 रुपए तथा (3) प्राथमिक शाला चंवर सराई से छोटा गैस टंकी चूल्हा सहित एक टेबल,चार नग प्लास्टिक कुर्सी व बर्तन कीमती करीब 10000 कुल जुमला कीमती करीब 96400 चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी के निशानदेही पर उक्त सामग्री की जप्त कर आरोपी को आज दिनांक 6.1 .2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मोबाइल दुकान और घर में भीषण आग,कोई जनहानि नहीं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

पैलेस रोड स्थित एक मोबाइल दुकान और उसके पास के घर में सोमवार की रात करीब 8.45 बजे अचानक आग लग गई। इस घटना में दुकान संचालक मनीष अग्रवाल और घर के मालिक विष्णु अग्रवाल को बड़ी राहत मिली,क्योंकि इस भीषण आगजनी में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि, मोबाइल दुकान और घर का सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक, मनीष अग्रवाल अपनी दुकान में मौजूद थे जब अचानक उन्हें जलने की गंध महसूस हुई। उन्होंने दुकान के चारों ओर देखा, लेकिन कोई विशेष कारण समझ में नहीं आया। जब वह बाहर निकले, तो देखा कि पास के घर में आग लग चुकी थी। जैसे ही उन्होंने यह देखा, आग मोबाइल दुकान में भी फैल गई और देखते ही देखते वह

विकराल रूप ले ली। इस घटना की सूचना आसपास के लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगभग दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन मोबाइल दुकान और घर का सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी के कारण का अंदेशा शॉर्ट-सर्किट से लगाया जा रहा है, हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मंगलवार को मोबाइल दुकान के संचालक और मकान मालिक ने इस घटना की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। आगजनी की इस घटना ने इलाके के लोगों को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन सभी ने राहत की सांस ली कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला,पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

शहर के मोमिनपुरा में एक युवक ने मारपीट कर तीन बार तलाक-तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि पति का संबंध किसी दूसरी महिला से है। पीड़िता ने पति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शेख आमिन हुसैन कोतवाली क्षेत्र के मोमिनपुरा का रहने वाला है और राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद संगठन का अध्यक्ष है। इसकी पत्नी शमा परवीन ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध है। इसका विरोध करने पर पति द्वारा मारपीट व गाली गलौज की जाती है। इसी बात को लेकर 16 दिसंबर 2025 को पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान शेख आमिन ने तीन बार तलाक बोलकर और मारपीट करते हुए पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी का कहना है कि उसने समझौते की कोशिश की, लेकिन पति ने यह कहते हुए रखने के लिए तैयार नहीं है कि उसने तीन तलाक दे दिया है। समझौता न होने पर पीड़िता 5 जनवरी को कोतवाली पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 296, 351 (3) और मुस्लिम विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया है।

मटर खाने की लालच में खेत में घुसे बच्चे,मिली तालिबानी सजा

-संवाददाता-
बलरामपुर,06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। खेत से मटर तोड़ने के आरोप में गांव के छोटे बच्चों को हाथ-पैर बांधकर बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान सजा देने का वीडियो भी बनाया गया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। पूरा मामला राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लडुवा का है। पीड़ित बच्चे के पिता ने इस मामले की शिकायत राजपुर थाने में दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि बच्चों की उम्र कम होने के बावजूद उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया,जिससे वे भयभीत और मानसिक रूप से आहत हैं। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर

दी है। थाना प्रभारी के अनुसार वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि बच्चों के साथ हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना सामने आने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

मध्य रात्रि सर्च अभियान में 25 किमी पीछा कर पकड़ा गया अवैध धान से लदा ट्रक,प्रशासन की सतत निगरानी से 750 बोरी अवैध धान जब्त

-संवाददाता-
बलरामपुर,06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के मार्गदर्शन में अवैध धान परिवहन पर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है जिसके अंतर्गत अवैध धान परिवहन,भंडारण में संलिप्त एवं कोचियों बिचौलियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में अनुविभाग वाड्रफनगर क्षेत्र अंतर्गत गत मध्य रात्रि अवैध धान परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। गिरवानी मार्ग के रास्ते उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ की ओर एक ट्रक में अवैध रूप से धान का परिवहन किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार उक्त ट्रक में लगभग 750 बोरी धान लोड थी, जिसे बिना वैध दस्तावेजों के ले जाया जा रहा था। मध्य रात्रि बैरियर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों द्वारा जब संदिग्ध ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, तो चालक वाहन

को लेकर मौके से फरार हो गया। जिसकी सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री नीर निधि नंदेहा के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए तहसीलदार वाड्रफनगर,तहसीलदार रघुनाथनगर,नायब तहसीलदार एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम द्वारा रात में ही सघन सर्च अभियान प्रारंभ किया गया। लगभग 25 किलोमीटर क्षेत्र में चलाए गए इस व्यापक सर्च अभियान के दौरान विभिन्न संभावित मार्गों,गांवों क्षेत्रों की गहन जांच की गई।

पति के मौत से परेशान महिला ने फांसी लगाकर दी जान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

शहर के बैरीपारा में 5 जनवरी की रात को अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा की पति की मृत्यु के बाद से वह काफी परेशान रहती थी। मामले में कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार रीना सिंह पति स्व. विरेंद्र सिंह उम्र 48 वर्ष कोतवाली क्षेत्र के केनाबांध बौरीपारा की रहने वाली है। इसका ससुर वृजमोहन सिंह ने पुलिस को बताया है कि इसके पति की मौत बीमारी से 14-15 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इस लिए वह काफी परेशान रहती थी। 5 जनवरी की रात को सह परिवार खाना खाकर अपने-अपने कमरे में सो रहे थे। 6 जनवरी की सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं निकली तो परिजन उसे अवाज लगाए, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। परिजर कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसे तो वह फांसी पर लटकी थी। परिजन की सूचन पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। पुलिस मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

प्रशासन चाहे कितना भी मुस्तैद हो,हम तो चूना लगाएंगे ही...

शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र में बड़ा घोटाला?

कागज़ों में 65 हजार क्विंटल...जमीनी हकीकत में धान नदारद...जांच से क्यों बच रहा केंद्र

- करोड़ों के भ्रष्टाचार कि आरोपी के हाथो में प्रबंधक की कमान...
- धान का भौतिक सत्यापन नहीं करोड़ों की फर्जी खरीदी कागजों पर...
- नियम कानून ताक पर,प्रशासन के मुस्तैदी के बावजूद बड़े घोटाले की आशंका

ओंकार पाण्डेय

सूरजपुर, 06 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

शिवप्रसाद नगर का धान खरीदी केंद्र एक बार फिर गंभीर आरोपों और सवालों के घेरे में है, स्थानीय किसानों,सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहां धान खरीदी के नाम पर कागजी आंकड़ों और वास्तविक भंडारण के बीच भारी अंतर बताया जा रहा है,शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र में घोटाले की बात हर वर्ष की भांति आम हो चली है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जितनी धान खरीदी दर्शाई जा रही है,क्या उतनी धान वास्तव में समिति के पास मौजूद भी है? जब से खरीदी केंद्र से डीओ कटना प्रारंभ हुआ है,और समिति से धान उठाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है,तब से बड़े पैमाने पर कागजों में फर्जी धान खरीदी को अंजाम दिया जा रहा है। इस वर्ष धान खरीदने के लिए सरकार और प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया था। प्रारंभिक स्तर पर टोकन की सीमित मात्रा कटने मात्र से ही लगभग अधिकांश किसानों का उपार्जित धान खरीदी किया जा चुका है, आलम यह है कि जो वास्तव में किसान है,वह अपना धान बेच चुके हैं, और अब उनके पास धान की उपलब्धता नहीं है, यह बात दीगर है कि चुनावी लाभ लेने के लिए सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी का मानक तय किया गया है,परंतु वास्तविकता यह है कि असामान्य भूमि संरचना और उन्नत तकनीक के अभाव में किसान औसतन 15-16 क्विंटल धान ही उपार्जित कर पाते हैं, हर वर्ष होता यह आया था की किसान अपने उपार्जित फसल को बेचने के बाद भी रकबा खाली रह जाता था,जिसमें व्यापारी, बिचौलिए और समिति के कर्मचारी राइसमिलों से मिलीभगत कर फर्जी धान खरीदी को अंजाम देते थे,फलस्वरुप धान खरीदी के अंत तक खरीदी की मात्रा लाखों मीट्रिक टन हो जाया करती थी। पर इस वर्ष प्रशासन की मुस्तैदी के चलते अधिकांश धान खरीदी केंद्रों में भ्रष्टाचार की यह व्यवस्था सक्रिय नहीं हो पाई है। परंतु सूत्रों के अनुसार 'आदतन लोग बाज नहीं' आते इस तर्ज पर शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र में फर्जी धान खरीदी का बड़ा भ्रष्टाचार करने की सूचना प्राप्त हुई है।

अंतिम चरण में 'उठाव' के साथ तेज हुआ खेल

धान खरीदी अपने अंतिम चरण में है, इसी दौरान उठाव (लिफ्टिंग) शुरू होते ही भ्रष्टाचार का कथित खेल तेज हो गया है, आरोप है कि धान केंद्र तक पहुंच नहीं रहा, लेकिन रिकॉर्ड में खरीदी पूरी दर्ज हो रही है, उठाव के नाम पर कागजी संतुलन बनाया जा रहा है। किसानों के रकबे पर पूरा टोकन तो काटा जा रहा है,परंतु समिति तक धान पहुंच नहीं रहा और सायं काल होते-होते प्रति दिवस पूरी खरीदी दर्शा दी जा रही है,जिन किसानों के पंजीयन अनुसार उनके खाते में खरीदी दर्शाइ जा रही है,उनके एटीएम और एडवांस चेक पहले ही रसूखदार व्यक्ति द्वारा जारी करवा लिया गया है, जिससे कि फर्जी धान खरीदी के रुपए आहरण में किसी प्रकार का व्यवधान ना आने पाये।

आंकड़े कुछ और, जमीन पर सच्चाई कुछ और

सूत्रों के मुताबिक शिव प्रसाद नगर धान खरीदी में अब तक लगभग 65,000 क्विंटल धान की खरीदी कागजों में दिखाई जा चुकी है, जबकि करीब 2,000 क्विंटल का उठाव भी दर्ज है, लेकिन केंद्र की वास्तविक स्थिति यह बताती है कि समिति परिसर में उतना धान मौजूद ही नहीं है,जितना धान खरीदी होना बताया जा रहा है। यदि इस समय भौतिक सत्यापन कराया जाए,तो खरीदी और स्टॉक में बड़ा अंतर सामने आ सकता है। सूत्रों के अनुसार शिवप्रसाद नगर धान खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है,और केवल कागजों में ही खरीदी को अंजाम दिया गया है।

खाली रकबे,भरे रिकॉर्ड, किसानों के नाम पर माफिया

स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप है कि कई किसानों के रकबे खाली पड़े हैं,फिर भी उन्हीं किसानों के नाम पर धान खरीदी दिखाई जा रही है,बताया जा रहा है कि धान माफिया किसानों के नाम का इस्तेमाल कर धान खपा रहा है,जिससे वास्तविक किसानों का हक़ प्रभावित हो रहा है और शासन को सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है,बड़ी मात्रा और बड़ी खरीदी के फर्जीवाड़े के लिए टोकन भी उन्हीं किसानों का काटा जा रहा है,जिससे फर्जी धान खरीदी करवा कर प्रत्यक्ष लाभ लिया जा सके। ऐसे में वास्तविक किसान चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

'हदीस' नामक धान माफिया का दबदबा

सूत्रों के अनुसार शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र में धान माफिया 'हदीस' का नाम खुलकर सामने आ रहा है। और यह पहली बार नहीं है, बल्कि कई वर्षों से यह व्यक्ति शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र में अपनी अपरोक्ष संदिग्ध भूमिका निभाते आ रहा है। आरोप हैं कि केंद्र प्रभारी से लेकर समिति प्रबंधक तक उसी के इशारों पर काम करते हैं,बिना तौल, बिना सख्त जांच सीधे धान चढ़ा दिया जाता है। किसे प्रभारी बनाना है,किसे हटाना है,फैसले भी उसी के प्रभाव में होते हैं,कहा जा रहा है कि यह नेटवर्क आज का नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। जिसकी वजह से यहां बार-बार केंद्र प्रभारी और समिति प्रबंधक बदलने की मांग उठती रही है,विगत कुछ वर्षों से इस व्यक्ति की एक करीबी महिला बतौर प्रबंधक समिति का कार्य देख रही हैं। जिन पर विगत वर्ष बड़े पैमाने पर पशु लोन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज किया गया था। जिसमें उक्त महिला को जेल तक जाना पड़ा था,बावजूद इसके इतने बड़े प्रकरण के बाद भी इस महिला को प्रबंधक का कमान देना पूरे सिस्टम को संदेह के घेरे में खड़ा करता है, प्रत्येक समिति में समिति प्रबंधक के अलावा धान खरीदी प्रभारी की भी भूमिका अहम होती है। शिवप्रसाद नगर समिति में विगत वर्ष समिति प्रबंधक के करोड़ों के घोटाले के उजागर होने के अलावा समिति में और भी कर्मचारी हैं, जो धान माफिया को परोक्ष अपरोक्ष रूप से लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी में एक नाम सोहराब का है,जो कि समिति में पदस्थ होने के साथ-साथ धान खरीदी में अहम भूमिका निभाता है। हदीस नामक व्यक्ति के साथ इसके गठजोड़ की भी चर्चाएं आम है। और सूत्रों के अनुसार इस पर भी फर्जी धान खरीदी के प्रकरण में संलिप्त होने की पूरी आशंका है।

धान खरीदी के आंकड़े फर्जी? जांच हो तो शिवप्रसाद नगर केंद्र के स्टॉक और रिकॉर्ड में मिल सकता है भारी अंतर

उठाव शुरू होते ही खुला धान घोटाले का खेल शिवप्रसाद नगर खरीदी केंद्र जांच से क्यों दूर?

खरीदी केंद्र या माफिया अड्डा? शिवप्रसाद नगर में धान पहुंचा बिना ही भुगतान का खेल

26 में खरीद, 31 में भुगतान! शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र पर माफिया राज के आरोप

- धान नहीं, सिर्फ एंट्री! शिवप्रसाद नगर खरीदी केंद्र में कागजी खरीदी का आरोप
- धान कम, संरक्षण ज्यादा? शिवप्रसाद नगर खरीदी केंद्र पर जांच की हिम्मत किसी में नहीं
- गोदाम खाली,रिकॉर्ड भरे शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र पर बड़ा सवाल
- सरकार खरीदे धान,माफिया बेचे कागज शिवप्रसाद नगर खरीदी केंद्र की असली तस्वीर

26 में खरीद,31 में भुगतान...सरकारी खजाने पर चोट- आरोपों के मुताबिक माफिया 25 प्रति किलो की दर से धान खरीदता है,लेकिन 31 प्रति किलो के सरकारी रेट से किसानों के खातों से भुगतान निकलवा लेता है,इसके लिए किसानों का एक संगठित गिरोह काम करता है,जो नाम उधार देने से लेकर फर्जी एंट्री तक में शामिल बताया जा रहा है। इस पूरे खेल में सरकारी खजाने को लाखों-करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

बोरियों में भी गड़बड़ी के आरोप- सिर्फ धान ही नहीं,बोरियों (सैक) को लेकर भी अनियमितताओं के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि धान पहुंचता नहीं, लेकिन बोरियां समिति से किसानों के नाम पर निकाल दी जाती हैं। बोरियों की घर-पकड़ (रिकवरी) भी नहीं हो रही।

जांच से उच्चों डर- प्रशासन पर भी सवाल सबसे गंभीर आरोप यह है कि अन्य धान खरीदी केंद्रों में जांच दल भेजे जा रहे हैं,कई समितियां में तो आलम यह है कि प्रशासनिक अधिकारी डेरा जमा कर बैठे हैं,एक दिन में कई कई फेरे लगा रहे हैं,दिन में,रात में अवैध धान पकड़कर प्रशासन के सुपुर्द कर रहे हैं, लेकिन शिवप्रसाद नगर ऐसा केंद्र बन गया है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की जांच की हिम्मत नहीं हो पा रही,सूत्रों का दावा है कि प्रशासन को सब कुछ पता होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही . यह मिलीभगत का परिणाम हो सकता है। यहां तक कि माफिया खुलेआम यह कहता फिर रहा है कि 'कलेक्टर,एसडीएम,तहसीलदार सब सेट हैं '—हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

पहले भी हो चुकी हैं कार्रवाइयां...

बताया जाता है कि इससे पहले भी धान खरीदी में अनियमितताएं सामने आई थीं,एक खरीदी प्रभारी पर अपराध दर्ज हुआ था,जेल जाने की नौबत तक आई थी, इसके बावजूद वही नेटवर्क आज भी सक्रिय बताया जा रहा है, जिससे सवाल उठता है कि कार्रवाई टिकाऊ क्यों नहीं हो पाती विगत सत्र में पशु लोन के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया था,जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और महिला प्रबंधक साधना कुशवाहा को जेल तक जाना पड़ा था। इतने बड़े पैमाने पर प्रकरण के उजागर होने के बाद भी ऐसे ही कर्मचारियों को कमान देना विभागीय उदासीनता का प्रतीक नजर आता है।

अब निगाहें प्रशासनिक जांच पर...

यदि इन गंभीर आरोपों के बाद भी भौतिक सत्यापन,स्टॉक मिलान और भुगतान जांच नहीं होती,तो यह संदेह और गहरा जाएगा कि कहीं यह केंद्र संरक्षण के घेरे में तो नहीं। अब देखना यह है कि खबर के प्रकाशन के बाद प्रशासन हरकत में आता है या नहीं,क्योंकि जांच हुई तो तय है कागज और गोदाम के बीच का फर्क सामने आएगा, और अगर नहीं हुई,तो आरोपों को और भी मजबूती मिलेगी कि धान खरीदी के नाम पर एक संगठित खेल बेखौफ चल रहा है,जो सरकार को करोड़ों का चूना लगाने में संलिप्त है।

यातायात जागरूकता लाने,जशपुर पुलिस ने ऑटो चालकों के माध्यम से निकाली ऑटो रैली यातायात नियमों का पालन करने हेतु आम नागरिकों को रैली के माध्यम से दिया संदेश

-संवाददाता-
जशपुरनगर,06 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

जशपुर जिले में सड़क हादसों में होने वाली अकाल मौत के आंकड़ों को कम करने और सडक़ दुर्घटनाओं में कमी लाने व आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने हेतु जशपुर पुलिस 01 से 31 जनवरी 2026 तक राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह मना रही है। इस अभियान के तहत् पुलिस के द्वारा आम नागरिकों के मध्य जाकर लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों, कॉलेजों व सार्वजानिक स्थानों में जाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के निर्देश व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर राकेश कुमार पाटनवार के नेतृत्व में ऑटो

चालकों के साथ,जशपुर शहर में रैली निकाली गई। यह ऑटो रैली एसडीओपी कार्यालय जशपुर से प्रारंभ हो कर, जिला मुख्यालय जशपुर के महाराजा चौक, सन्ना तिराहा, बिरसा मुंडा चौक, जैन मंदिर तिराहा, बस स्टैंड, पुरानी टोली होते हुए, एसडीओपी कार्यालय जशपुर में समाप्त हुई। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि, आवश्यकता से अधिक सवारी न बैठाया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस व इंश्योरेंस अपडेट होना चाहिए, नशे की हालत में कतई वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें व दूसरों को भी पालन हेतु प्रेरित करें।

कहीं दुर्घटना घटित होने परए भागे नहीं, बल्कि अच्छे नागरिक होने का परिचय दें : जशपुर पुलिस की ओर से जिले के आम नागरिकों से अपील की गई कि, लोग यातायात नियमों का पालन करें, बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन न चलाएं, ओवर स्पीड, नशे में वाहन कतई वाहन न चलाएं,ऐसा करने से खुद व दूसरों की जान खतरे में पड़ सकती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़कें चढ़ रही हैं भ्रष्टाचार की भेंट,सड़क बनते ही उखड़ गई यह है सड़क की गुणवत्ता

-संवाददाता-
खड़गवां,06 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

खड़गवां विकास खंड में निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण छत्तीसगढ़ शासन में भाजपा की विष्णु देव साय की सरकार में सुशासन के दावे सिर्फ खोखले साबित हो रहे हैं और हकीकत जमीन पर दम तोड़ते नजर आ रही हैं। विकास खंड में हालात ऐसे बन हुए हैं कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। ना ही ठेकेदारों को किसी भी कार्यवाही का डर है, ना ही अधिकारियों की अपनी जवाबदेही की चिंता है। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास के नाम पर खुलेआम लूट का खुला खेल चल रहा है। भ्रष्टाचार का ताज़ा और प्रमाणित मामला सामने आया है एमसीबी जिले के खड़गवां विकास खंड में जहां ग्राम पंचायत कदरेवा, भूकभकी और बरमपुर में सड़क

मरम्मत के नाम पर जनता के टैक्स के पैसों का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है।

जिन सड़कों को मरम्मत के बाद वर्षों चलना चाहिए वह महज एक दिन भी नहीं टिक पा रही है। ठेकेदार ने सड़क तो बनाई और महज ही कुछ ही घंटों में वह धूल की तरह उड़ गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता इतनी घटिया है कि ग्रामीण उंगलियों से डामर उखाड़ रहे हैं। इस सड़क निर्माण कार्य में डामर की सही मात्रा का मिश्रण नहीं किया गया है और ना ही निर्धारित मापदंडों का एवं तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।सड़क की मोटाई सिर्फ सही नहीं है और मिट्टी के ऊपर सीधे डामर बिछाया गया है जबकि मिट्टी की पूर्ण सफाई करके बेस तैयार कर रोलर से रोलिंग करने के पश्चात सडक पर डामरीकरण का कार्य किया जाना होता है जो नहीं किया गया है सडक निर्माण कार्य सड़क पर पड़ी मिट्टी के उपर सीधा डामरीकरण कार्य कर दिया गया है।

ठेकेदार और अधिकारियों की सेटिंग से हो रहा है निर्माण कार्य : जब ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का विरोध किया तो ठेकेदार के सड़क निर्माण कार्य में लगे लोगों ने कहा की सारा खेल सेटिंग पर चल रहा है जाओ जो करना है कर लो।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मौन नहीं, खुली सहमति है : अधिकारियों के सब कुछ सामने होने के बावजूद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी पूरी तरह मौन बनकर कार्य को अंजाम दे रहे हैं। चुप रहने का नहीं बल्कि खुले संरक्षण की गवाही दे रहा है।

जनता के टैक्स के पैसे की खुलेआम लूट हुई है : फिर भी कोई कार्यवाही का नहीं होना बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार को अभयदान देना है। केंद्र और राज्य-दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार होने के कारण ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारियों को खुला समर्थन मिल चुका है की जनता का पैसो को लूटो और घटिया निर्माण कार्य करो।

केतका जंगल में अवैध उत्खनन

स्कूल के पास दर्जनों क्रेशर, आदिवासी गांव देवीपुर प्रदूषण की गिरफ्त में

स्कूल के साए में क्रेशर,जंगल में उत्खनन,आदिवासी गांव देवीपुर दमघोंटू प्रदूषण की गिरफ्त में

7 किलोमीटर दूर प्रशासन, 200 मीटर पर क्रेशर, देवीपुर के बच्चों की सांसों पर संकट

केतका जंगल उजड़ रहा,देवीपुर घुट रहाः आदिवासी इलाक़े में अवैध उत्खनन का खेल

जहाँ पढ़ाई होनी थी,वहाँ उड़ रही धूलः स्कूल के पास क्रेशर बने खतरा

स्कूल के आसपास क्रेशरों का जाल,बच्चों की सेहत पर सीधा असर

स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब विद्यालय से मात्र लगभग 200 मीटर की दूरी पर दर्जनों गिट्टी क्रेशर प्लांट संचालित पाए जाते हैं,स्कूल तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग इन्हीं क्रेशरों के बीच से गुजरता है, जहाँ दिन-रात भारी ट्रकों और ट्रैक्टरों की आवाजाही जारी रहती है। इससे पूरे इलाके में धूल, शोर और कंपन फैल रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है।

सांस,आंख और त्वचा रोगों में बढ़ोत्तरी...

शिवसेना जिला प्रमुख विष्णु वैष्णव ने बताया कि लगातार प्रदूषण के कारण गांव में दमा,सांस की बीमारी,आंखों में जलन,त्वचा रोग जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसके बावजूद न तो प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की जांच हो रही है और न ही नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

केतका जंगल में अवैध उत्खनन, वन संपदा पर हमला

देवीपुर से सटे केतका जंगल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उत्खनन का आरोप भी सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि भारी मशीनों के संचालन से पेड़ों की कटाई,वन भूमि का क्षरण और पर्यावरण संतुलन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जंगल क्षेत्र में उत्खनन के लिए वैधानिक अनुमति ली गई है? यदि ली गई है तो उसकी शर्तों का पालन क्यों नहीं हो रहा?

डर और दबाव में आदिवासी ग्रामीण

गांव में अधिकांशतः आदिवासी एवं मूल निवासी परिवार रहते हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि क्रेशर और उत्खनन से जुड़े प्रभावशाली लोग उन्हें डराते-धमकाते हैं,जिससे वे खुलकर विरोध नहीं कर पाते,वहीं,चर्चा है कि पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक कुछ अधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि आर्थिक लाभ के चलते आंखें मूंदे हुए हैं।

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, ये हैं प्रमुख मांगें

शिवसेना (उद्धव गुट) ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि...

- विद्यालय परिसर से तत्काल ट्रांसफार्मर हटाया जाए,
- क्रेशर प्लांटों और जंगल में हो रहे उत्खनन की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए...
- पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो...
- बच्चों और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की मेडिकल जांच कराई जाए...

देवीपुर में पर्यावरण आपदा के हालात, शिवसेना ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

जिला मुख्यालय से महज़ 7 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी बहुल ग्राम देवीपुर आज पर्यावरणीय संकट,प्रशासनिक उदासीनता और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे का प्रतीक बनता जा रहा है। गांव की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला,जहाँ रोज़ सैकड़ों बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं,उसी विद्यालय परिसर के खेल मैदान में उच्च क्षमता का विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित है। विशेषज्ञों के अनुसार यह किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है,लेकिन संबंधित विभागों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है,ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला प्रमुख विष्णु वैष्णव,ग्रामीण जिला प्रमुख हेमंत कुमार महंत,ब्लॉक प्रमुख मोहन सिंह टेकाम,महिला जिला अध्यक्ष पिंकी पटेल,बालकुंवर राजवाड़े,रजनी सिंह सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक और ग्रामीण मौजूद रहे,शिवसेना नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि यदि प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए,तो देवीपुर और आसपास का इलाका गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय आपदा की ओर बढ़ जाएगा,जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी।

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ भाजपा का भव्य युवा सम्मेलन संपन्न

-संवाददाता-
कोरिया,06 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवा सम्मेलन का आयोजन सांस्कृतिक भवन, बैकुंठपुर में भव्य रूप से संपन्न हुआ। सम्मेलन में भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी एवं जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम की गरिमामयी उपस्थिति रही, कार्यक्रम के पश्चात प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम का करमा नृत्य, ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया।

युवा मोर्चा पार्टी की ताकतः रामविचार नेताम

सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि युवा मोर्चा भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है और देश के परिवर्तन में युवाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है, उन्होंने कहा कि भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने कार्य, उत्पाद और सोच में स्वदेशी भाव को अपनाना होगा, मंत्री श्री नेताम ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में युवाओं की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने आह्वान किया कि युवा अपनी ऊर्जा, कौशल और नवाचार को समाज एवं राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करें।

आने वाला समय युवाओं का हैः रेणुका सिंह

भारतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि आज युवाओं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे आप सभी मिलकर पूरा कर सकते हैं, आने वाला समय युवाओं का है और यही पीढ़ी देश को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत उज्जवल भविष्य की नींवः देवेन्द्र तिवारी

भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत देश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है,उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय भारत ने अपनी वैक्सीन बनाकर न केवल अपने नागरिकों की रक्षा की, बल्कि पूरी दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत की शक्ति को सिद्ध किया।

गांव-गांव तक पहुंचेगा आत्मनिर्भर भारत का संदेश

भाजयुमो जिलाध्यक्ष सतेन्द्र राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर युवा मोर्चा कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे और इस अभियान को जन-आंदोलन बनाएंगे। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णबिहारी जायसवाल, पूर्व नपाध्यक्ष शैलेष शिवहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा,नगर पालिका अध्यक्ष अरूण जायसवाल सहित भाजपा,भाजयुमो,महिला मोर्चा के पदाधिकारी,जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के अनुबंध निरस्त कर... ब्लैक लिस्ट करने हेतु किया निर्देशित

-संवाददाता-
कोरबा,06 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर कुणाल दुदावत कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभिन्न निर्माण विभागों की बैठक लेकर प्रगतिरत निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण कराने हेतु सभी निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही निर्माण कार्यों के गुणवत्ता पर किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, सेतु, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य निर्माण विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रगतिरत निर्माण व मरम्मत कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए तेजी से प्रगति लाने एवं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग अंतर्गत निर्माण किये जा रहे अनेक सड़क,स्कूल भवन,कॉलेज भवन सहित अन्य प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्य में गंभीरता से तेजी लाने एवं समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तार हेतु किए जा रहे निर्माण कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराने के लिए कहा। कॉलेज व विद्यालय भवन के कार्य को अगले शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले पूर्ण कराने निर्देशित किया, साथ ही मरम्मत कार्यों को भी शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए कहा। उन्होंने सभी निर्माण विभागों को प्रगतिरत सभी स्थानों में समान्तर कार्य प्रारंभ कराने, मशीनरी एवं श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की बात कही,साथ ही निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने व अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले एजेंसियों पर सख्ती से कार्यवाही करते हुए अनुबंध निरस्त करने एवं ब्लैक लिस्ट करने हेतु निर्देशित किया है ।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर

निविदा आमंत्रण तिथि - 02.01.2026

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें http://eproc.cgstate.gov.in
02. संबंधित संभाग- जशपुर संभाग
03. स.क्र. 1'द' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार
04. ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि स.क्र. 1 - 23.01.2026

स0 क्र0	एन.आई.टी. क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	229	शासकीय महाविद्यालय दुलदुला जिला जशपुर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य एवं शासकीय महाविद्यालय तपकरा जिला जशपुर में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य । (प्रथम आमंत्रण)	61.68

जी नंबर-252605824/4

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर

महिला सुरक्षा,मानव तस्करी पर चलाया गया जागरूकता अभियान

-संवाददाता-
कोरबा,06 जनवरी 2026
(घटती-घटना)।

कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक संयुक्त टीम ने रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान फोरम मॉल परिसर में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा संबंधी कानून, मानव तस्करी की रोकथाम और यातायात सुरक्षा के बारे में जानकारी देना था। इस अभियान में चौकी प्रभारी सीएसईबी भीमसेन, यातायात विभाग से सहायक उप निरीक्षक मनोज राठौर, पुलिस चौकी मानिकपुर से सहायक उप निरीक्षक कुलदीप तिवारी और महिला थाना प्रभारी भावना खंडारे अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। साइबर सेल की टीम और अन्य महिला पुलिस अधिकारी भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल थे । अधिकारियों ने महिला सुरक्षा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम और पॉक्सो एक्ट जैसे महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने महिला हेल्पलाइन 1091, आपातकालीन सेवा 112 और साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों पर भी प्रकाश डाला। नागरिकों को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना,छेड़छाड़,ऑनलाइन धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई। मानव तस्करी के खतरों के बारे में विस्तार से बताते हुए लोगों को संदिग्ध नेटवर्क की पहचान करने और पुलिस को सूचित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यातायात सुरक्षा के तहत हेलमेट के उपयोग, सीटबेल्ट लगाने, गति सीमा का पालन करने और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के दुष्परिणामों पर विशेष जोर दिया गया।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा(छ0ग0)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. ...../अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक तिफन आ0 रामसाय वगै0 जाति उरांव निवासी बिशुनपुरखुर्द तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आध्यि की भूमि स्थित ग्राम बिशुनपुरखुर्द तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) खसरा नंबर 93/1 रकबा 0.020 हे0 में से 0.010 हे0 भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी-1, खसरा, रजिस्ट्री की प्रति, आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है ।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 27/01/2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 05 /01 /2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 ,जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0क0... /ब-121/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका संगीता सिंह पति गोपाल सिंह, निवासी ग्राम भगवानपुरखुर्द, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम भगवानपुरखुर्द स्थित व्यपवर्तित भूमि खसरा नंबर 95/2 रकबा 0.080 में से रकबा 0.040 हे0 भूमि अपने निजी कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण अनावेदक धीरेन्द्र प्रसाद आ0 स्व0 कन्हैया लाल जायसवाल, निवासी ग्राम बतरा, तहसील भैयाथान, जिला-सूरजपुर (छ0ग0) को रू0 4,70,000/- (चार लाख सत्तर हजार रूपये) में विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 16/01/2026 से पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 14/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-02

न्यायालय नजूल अधिकारी,अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0ज0/.../अ-20 (3) /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक संतोष कुमार सोनी 0 स्व0 रामसुन्दर प्रसाद सोनी जाति सोनार आयु 48 वर्ष निवासी सत्तीपारा अम्बिकापुर, थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा शीट नम्बर -02 मोहल्ला सत्तीपारा नेहरूवार्ड नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 621/48 रकबा 0.02 एकड़ भूमि को अनावेदक / क्रेता प्रियका सोनी पति प्रमोद सोनी आयु 31 वर्ष जाति सोनार निवासी नेहरूवार्ड 25 सत्तीपारा अम्बिकापुर, थाना व तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास विक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 21/01/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक - 22/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

सील — नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,सरगुजा

न्यायालय नजूल अधिकारी,अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़

रा0प्र0ज0/.../ब-121 /2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं, कि आवेदक उमेश कुमार अग्रवाल आ0 लालचंद अग्रवाल निवासी नेहरूपार्क रोड सूरजपुर तहसील व जिला सूरजपुर छ0ग0 के द्वारा शीट नम्बर - 04 प्रतापपुरनाका, नगर अम्बिकापुर स्थित प्लाट नम्बर 2010/120 रकवा 672 वर्गफीट भूमि पर प्रस्तावित नक्शानुसार अनुसार भूतल पर रकबा 42.65 वर्गमीटर प्रथम तल पर रकबा 35.07 वर्गमीटर, पर व्यवसायिक एवं आवासीय भवन निर्माण कराने हेतु आवेदन पत्र मय मेन्टेनेन्स खसरा एवं प्रस्तावित ब्लूप्रिंट नक्शा की प्रति सहित आवेदन पत्र न्यायालय अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा छ0ग0 में प्रस्तुत किया है जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय प्राप्त हुआ है ।

उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 07/01/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 15/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,सरगुजा

CMYK

बैकुंठपुर नगर पालिका सीएमओ को पटना नगर पंचायत का भी वित्तीय प्रभार... सुशासन या जुगाड़ तंत्र ? उठे गंभीर सवाल

एक अधिकारी,दो नगरीय निकाय, व्यवस्था सुधरेगी या जुगाड़ और गहराएगा ?

जब एक नगर पालिका नहीं संभल रही,तो नगर पंचायत पटना किस भरोसे ?

वित्तीय प्रभार का खेल ? पटना नगर पंचायत में फंड और फैसलों पर सवाल

सुशासन या स्थानीय जुगाड़,दो नगरीय निकायों की चाबी एक ही हाथ में क्यों ?

जनप्रतिनिधि असंतुष्ट,फिर भी दोहरी जिम्मेदारीः प्रशासनिक फैसले कटघरे में...

जब एक नगर पालिका नहीं संभल पा रही, तो दूसरी कैसे संभलेगी ?

यह तर्क समझ से परे है कि जो अधिकारी एक नगर पालिका की व्यवस्था पटरी पर नहीं ला सका, वह नवगठित नगर पंचायत की जिम्मेदारी कैसे बेहतर ढंग से निभा पाएगा? नगर पंचायत पटना एक नया निकाय है, जहां नीति, योजना और पारदर्शी शुरुआत की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन वहां भी वही चेहरा, वही कार्यशैली और वही अधिकारी तो बदलाव किस बात का?

वित्तीय प्रभारः संयोग या उद्देश्य ?

सबसे संवेदनशील सवाल वित्तीय प्रभार को लेकर है, क्या पटना नगर पंचायत में अधिक फंड की संभावित आवक को देखते हुए ही एक ही अधिकारी को वित्तीय जिम्मेदारी सौंपी गई है? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक निर्णय है, या फिर जहां ज्यादा राशि, वहीं वही अधिकारी जैसा संदेश देने वाला फैसला?

-रवि सिंह-

बैकुण्ठपुर/पटना,06 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के नवगठित पटना नगर पंचायत को जब कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूर्व सीएमओ से मुक्त किया गया, तब यह उम्मीद जगी कि अब यहां नए नेतृत्व के साथ स्वच्छ और पारदर्शी नगरीय प्रशासन की शुरुआत होगी। लेकिन यह उम्मीद ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि बैकुंठपुर नगर पालिका के वर्तमान सीएमओ को ही पटना नगर पंचायत का भी वित्तीय प्रभार सौंप दिया गया है, वैसे ही प्रशासनिक हलकों और आमजन के बीच एक तीखा सवाल खड़ा हो गया यह सुशासन है या फिर जुगाड़ तंत्र?

पटना नगर पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के बाद यदि वही पुरानी कार्यशैली और दोहरे प्रभार की व्यवस्था लागू की जाती है, तो यह नवगठित निकाय के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगाता है,आज जरूरत है स्पष्टता, पारदर्शिता और स्वतंत्र प्रशासनिक ढांचे की न कि ऐसे फैसलों की,जो सुशासन से ज्यादा जुगाड़ की बू दें, अब देखना यह होगा कि शासन और नगरीय प्रशासन विभाग इस फैसले पर पुनर्विचार करता है या नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक अधिकारी का नहीं,बल्कि दो नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली और जनता के भरोसे का है, यह मामला सिर्फ एक अधिकारी की पोस्टिंग का नहीं है,यह सवाल है प्रशासनिक पारदर्शिता का जवाबदेही का और नवगठित नगर पंचायत पटना के भविष्य का अगर अभी स्पष्टता नहीं लाई गई,तो यह निर्णय आने वाले समय में बड़े विवाद और अविश्वास की वजह बन सकता है।

सवाल जो जवाब चाहते हैं...

क्या यह निर्णय सुशासन की भावना से लिया गया है?

या फिर स्थानीय प्रभाव और जुगाड़ का परिणाम है?

क्या नगरीय प्रशासन विभाग इस फैसले की समीक्षा करेगा?

और सबसे अहम–पटना नगर पंचायत की व्यवस्था किस भरोसे सुधरेगी?

एक अधिकारी,दो नगरीय निकाय,व्यवस्था सुधरेगी या और उलझेगी?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक स्थानीय अधिकारी के पास एक साथ नगर पालिका और नगर पंचायत की जिम्मेदारी देने से व्यवस्था वास्तव में सुधरेगी या और बिगड़ेगी? जब एक नगर पालिका की कार्यप्रणाली पहले से ही सवालों के घेरे में हो,विकास कार्यों की रफ्तार पर असंतोष हो और जनप्रतिनिधि भीतरखाने नाराज़ हों,तो उसी अधिकारी को दूसरे नगरीय निकाय की जिम्मेदारी देना प्रशासनिक विवेक पर सवाल खड़े करता है।

नवगठित नगर पंचायत, लेकिन पुरानी व्यवस्था ?

पटना नगर पंचायत हाल ही में गठित नगरीय निकाय है, स्वाभाविक है कि यहां विकास कार्यों के लिए धन की आवक आने वाले समय में बढ़ेगी,ऐसे में अलग,स्वतंत्र और पूर्णकालिक सीएमओ की नियुक्ति अपेक्षित थी, लेकिन इसके बजाय बैकुंठपुर के सीएमओ को ही दोहरी जिम्मेदारी सौंप दी गई,प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि एक अधिकारी के पास दो नगरीय निकायों का वित्तीय नियंत्रण होना खासकर तब,जब उनमें से एक नवगठित और फंड-समृद्ध होने जा रहा हो,हितों के टकराव और निगरानी की कमी को जन्म दे सकता है।

'जुगाड़' की चर्चा क्यों?

स्थानीय चर्चाओं में यह बात जोर पकड़ रही है कि बैकुंठपुर सीएमओ स्थानीय निवासी हैं और उनका संबंध एक प्रभावशाली परिवार से बताया जाता है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या इसी स्थानीय प्रभाव और पहुंच के चलते उन्हें अपने ही गृह जिले में दो-दो नगरीय निकायों का प्रभार मिल गया? जबकि नगरीय प्रशासन विभाग में सीएमओ की कमी इतनी भी नहीं बताई जाती कि ऐसी मजबूरी में दोहरा प्रभार देना पड़े, यही कारण है कि इसे प्रशासनिक विवेक से ज्यादा 'जुगाड़' के रूप में देखा जा रहा है।

बैकुंठपुर में असंतोष,पटना की जिम्मेदारी कैसे?

सबसे बड़ा और चिंताजनक पहलू यह है कि बैकुंठपुर नगर पालिका में ही सीएमओ के कार्यकाल को लेकर संतोष का माहौल नहीं है, स्थानीय स्तर पर लगातार यह आरोप लगते रहे हैं कि नगर पालिका की व्यवस्था पटरी पर नहीं है, विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता पर सवाल हैं, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक भी भीतर ही भीतर असंतुष्ट हैं, लेकिन स्थानीय होने के कारण यह विरोध खुलकर सामने नहीं आ पा रहा, जो अक्सर दबा दिया जाता है, अब सवाल यह है कि जब एक नगर पालिका की व्यवस्था नहीं सुधर पा रही, तो नवगठित नगर पंचायत पटना की जिम्मेदारी कैसे संभाली जाएगी?

असंतोष दबा है,खत्म नहीं हुआ

नगर पालिका बैकुंठपुर में जनप्रतिनिधि,पार्षद और आम नागरिक इस अधिकारी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं बताए जाते,लेकिन स्थानीय होने के कारण विरोध खुलकर सामने नहीं आ पा रहा,अब यही सवाल पटना नगर पंचायत को लेकर उठ रहा है अगर बैकुंठपुर में असंतोष दबा हुआ है,तो पटना में संतुष्टि किस भरोसे पैदा होगी?

सुशासन बनाम जुगाड़,फैसला कौन करेगा?

यदि नगरीय प्रशासन विभाग के पास सीएमओ की संख्या पर्याप्त है,तो फिर एक स्थानीय अधिकारी को गृह जिले में दो-दो नगरीय निकायों का प्रभार देना समझ से परे है, यह निर्णय सुशासन की मंशा से लिया गया या स्थानीय जुगाड़ और प्रभाव के कारण,इसका जवाब अब प्रशासन को देना होगा।

वित्तीय प्रभार पर खास नजर

इस पूरे घटनाक्रम में 'वित्तीय प्रभार' शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में है, राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह सवाल तैर रहा है कि क्या पटना नगर पंचायत में अधिक फंड आने की संभावना को देखते हुए ही यह प्रभार सौंपा गया? क्या एक ही अधिकारी के हाथ में दो नगरीय निकायों का वित्तीय नियंत्रण देना उचित है? यदि पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है, तो ऐसे मामलों में स्वतंत्र पदस्थापना ही बेहतर मानी जाती है।

कोरिया जन सहयोग समिति की बैठक संपन्न

वरिष्ठ कानूनी सलाहकार एवं मीडिया प्रतिनिधियों की रही उपस्थिति

बैठक में उपस्थित प्रमुख लोग...

प्रेस एंड मीडिया एसोसिएशन से राजन पाण्डेय,वरिष्ठ कानूनी सलाहकार रजा अली अंसारी,जयचंद सोनपाकर,राजू साहू,जयप्रकाश राजवाड़े,संतोष राजवाड़े,सोनेलाल राजवाड़े,बालकरन सोनपाकर,उमाशंकर राजवाड़े, राजेन्द्र कुमार, दिनेश,रमेश राजवाड़े, उमेश कुमार, नरेंद्र कुमार, अनिल कुमार,फलेंद्र कुमार,करण साय,अर्जुन कुमार,बलराम,देव नारायण, बृजलाल परिहत,संतोष,अक्षय कुमार,सुंदर राजवाड़े सहित अनेक सदस्य, स्थानीय बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

सोनहत ब्लॉक की मूलभूत समस्याओं पर छिड़ी गंभीर चर्चा,प्रशासन को सौंपा जाएगा ज्ञापन

बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे...

पेयजल संकट-वनांचल एवं दूरस्थ ग्रामों में गंभीर जल संकट पर चिंता जताई गई। कई हैंडपंपों के खराब होने,जल जीवन मिशन के कार्यों में अत्यधिक देरी तथा पाइपलाइन विस्तार की धीमी गति को प्रमुख समस्या बताया गया।

स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव-सोनहत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और लंबे समय से बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन का मुद्दा विशेष रूप से उठाया गया।

सड़क एवं कनेक्टिविटी-रामगढ़-कोटाडोल सड़क,भलुवार-रजपुरी मार्ग,बदरा-बंशीपुर मार्ग सहित सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने वाली जर्जर सड़कों की मरम्मत, सोनहत तहसील जनपद नर्सरी मार्ग की मरम्मत तथा लंबित सीसी सड़क,भवन और मिनी स्टेडियम निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग रखी गई।

वनांचल में अधूरा विद्युतीकरण-कचोहर, बंशीपुर,चंदाहा,नावटोला,निग्नोहर,तंजरा सहित ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य जल्द पूरा कर विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

मोबाइल कनेक्टिविटी-रामगढ़ क्षेत्र की 7 ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क सुविधा शुरू करने और बंद पड़े मोबाइल टावरों को चालू कराने की मांग पर विस्तृत चर्चा हुई।

-संवाददाता-

कोरिया,06 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जन सहयोग समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सोनहत अंतर्गत अमहर जलाशय के समीप आयोजित की गई,बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने की,इस अवसर पर वरिष्ठ कानूनी सलाहकार रजा अली अंसारी एवं अधिवक्ता जयचंद सोनपाकर विशेष रूप से उपस्थित रहे,बैठक में सोनहत ब्लॉक की ज्वलंत और मूलभूत समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु एक विस्तृत मांग-पत्र (ज्ञापन) शीघ्र ही जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों को सौंपा जाएगा,बैठक में सोनहत ब्लॉक की जमीनी समस्याओं को लेकर स्पष्ट रणनीति तय की गई। अब सभी की निगाहें 28 जनवरी को प्रस्तावित ज्ञापन और उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं।

राजनीति से ऊपर उठकर जनहित ही हमारा संकल्पः पुष्पेंद्र राजवाड़े

समिति अध्यक्ष पुष्पेंद्र राजवाड़े ने कहा कि सोनहत ब्लॉक प्राकृतिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। समिति का उद्देश्य राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों को शासनङ्कप्रशासन तक मजबूती से पहुंचाना और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित कराना है।

निःशुल्क विधिक सलाह

वरिष्ठ अधिवक्ता रजा अली अंसारी ने उपस्थित सदस्यों को विभिन्न मुद्दों पर विधिक मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए यदि कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़े तो समिति पूरी तरह तैयार है। सार्थक संवाद और संवैधानिक तरीकों से सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे।

28 जनवरी को ज्ञापन सौंपने का प्रस्तावः जयचंद सोनपाकर-

समिति के कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता जयचंद सोनपाकर ने जानकारी दी कि बैठक के अंत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है कि 28 जनवरी को सोनहत में ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, इस दौरान समिति के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं लेकर सोनहत पहुंचेंगे, सभा के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन में समस्याओं के समय-सीमा के भीतर समाधान की स्पष्ट मांग की जाएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्य, मीडिया प्रतिनिधि और वरिष्ठ कानूनी सलाहकार उपस्थित रहेंगे।

प्रेस एवं पत्रकार संगठनों से सहयोग की अपील

बैठक में समिति पदाधिकारियों ने प्रेस एंड मीडिया एसोसिएशन सहित समस्त पत्रकार संगठनों से क्षेत्रीय समस्याओं को प्रमुखता से सामने लाने और उनके निराकरण में सहयोग की अपील की।

CMYK

हार्दिक पांड्या ने गर्लफ्रेंड को अमिताभ बच्चन से मिलवाया

वायरल वीडियो जीत रहा लोगों का दिल

हार्दिक पांड्या और महिका शर्मा ने अक्टूबर 2025 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया। हाल ही में एक इवेंट में हार्दिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन से मिलवाया। ये वीडियो वायरल हो गया और अब इस पर यूजर्स अपने रिएक्शन दे रहे हैं।

मुंबई में एक ग्लैमरस शाम इंटरनेट पर वायरल हो गई, जब क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को अमिताभ बच्चन से मिलवाया। एक इनसाइड वीडियो में, जो अब ङ्क पर वायरल हो गया है,अमिताभ बच्चन हार्दिक पांड्या को गर्मजोशी से गले लगाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ही देर बाद, वह माहिका की ओर मुड़ते हैं और उन्हें दिग्गज एक्टर से मिलवाते हैं। माहिका उनसे हाथ मिलाकर जवाब देती हैं।

वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद,इंटरनेट यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी। एक यूजर ने लिखा,हार्दिक पांड्या को महिका शर्मा को अमिताभ बच्चन से मिलवाते देखना कितना खास पल था। इसमें एक साथ क्लास, सम्मान और सच्चा प्यार सब कुछ दिखा। एक और यूजर ने कहा, इतने बड़े स्टेज पर माहीका को लेजेंड अमिताभ बच्चन से मिलवाना हार्दिक का असली कैरेक्टर दिखाता है।

स्टाइलिश अंदाज में कपल ने की एंट्री

इस कपल ने इवेंट में स्टाइलिश एंट्री की, उन्होंने मैचिंग ब्लैक आउटफिट पहने थे। हार्दिक एक टेलर्ड ब्लैक सूट में बहुत अच्छे लग रहे थे,वहीं माहीका ने एक एलिगेंट ब्लैक ड्रेस में उन्हें परफेक्टली कॉम्प्लिमेंट किया।

हार्दिक और माहीका के रिश्ते को लेकर महीनों से अटकलें लगाई जा रही थीं, जिसे सोशल मीडिया इंटरैक्शन और साथ में घूमने-फिरने की तस्वीरों ने और हवा दी। हालांकि, क्रिकेटर ने अक्टूबर 2025 में, अपने 32वें जन्मदिन से ठीक पहले अपनी प्राइवेट बीच छुट्टियों की इंटीमेट तस्वीरें और वीडियो शेयर करके इन अफवाहों पर विराम लगा दिया और अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया। इन पोस्ट में कपल की एक साथ पूजा करते हुए तस्वीरें भी शामिल थीं।

कौन हैं माहीका शर्मा?

24 साल की माहिका शर्मा एक मॉडल हैं, जिन्होंने जाने-माने डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया है। उनके इंस्टाग्राम बायो में उन्हें जी क्यू बेस्ट ड्रेस्ड - इंडिया की अगली सुपरमॉडल और ईली मॉडल ऑफ द सीजन बताया गया है।

अटक गई थलापति विजय की जन नायकन,रिलीज से पहले सेंसर में फंसी

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय का नाम इन दिनों उनकी अपकमिंग मूवी जन नायकन को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब खबर रही है कि इस पॉलिटिकल थ्रिलर पर सेंसर बोर्ड ने शिकंजा कसा है। साउथ सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता विजय जोसेफ यानी थलापति विजय की अगली फिल्म का नाम जन नायकन है। हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है और हर कोई इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन रिलीज से पहले जन नायकन चर्चा में आ गई है और फिल्म के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट को लेकर पेंच फंस गया है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के लिए अटकी जन नायकन

थलापति विजय की जन नायकन को 9 जनवरी पोंगल के अवसर को मद्देनजर रखते हुए सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। एक्टर की आखिरी मूवी को लेकर सिनेप्रेमियों में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। लेकिन अब जो खबर आ रही है,उससे फैंस की चिंता बढ़ सकती है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार विजय की जन नायकन को अभी भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड की ओर से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। साथ ही बोर्ड ने ने अब मद्रास हाई कोर्ट को बताया है कि फिल्म की समीक्षा इस बार एक नई कमेटी द्वारा फिर से की जाएगी। गौरतलब है कि जन नायकन के मेकर्स ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था,क्योंकि पिछले एक महीने से जन नायकन सेंसर सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही है। मंगलवार 6 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सेंसर बोर्ड ने अपना पक्ष रखा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 7 जनवरी को दोपहर में होगी,जबकि 9 जनवरी को मूवी रिलीज होनी है। इस तरह से अपनी रिलीज को लेकर फिलहाल थलापति विजय की मूवी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।

बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी से होगा जन नायकन का क्लैश

अगर थलापति विजय की जन नायकन 9 जनवरी को रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर इसकी राह आसान नहीं होगी। क्योंकि उसी दिन साउथ सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब भी सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। ऐसे में सिनेप्रेमियों को एक जबरदस्त बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिल सकता है।

मुन्ना भाई 3 के साथ लौटेंगे संजय दत्त

डॉ अस्थाना ने शेयर की ऐसी डिटेल्स, खुशी से झूमने लगेंगे फैंस

मुन्नाभाई राजकुमार हिरानी की सफल फ्रेंचाइजी में से एक है। इस फिल्म के अब तक दो पार्ट्स आ चुके हैं। फैंस लंबे समय से फिल्म के तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में अब अभिनेता बमन ईरानी ने एक ऐसा अपडेट शेयर किया है,जिसे सुनकर फैंस की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच जाएगी। मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्नाभाई के बाद इसकी तीसरी फ्रेंचाइजी का इंतजार न जाने कब से कर रहे हैं। बीते दिनों अरशद वारसी ने जब ये बताया था कि राजकुमार हिरानी मुन्ना भाई की तीसरी इंस्टॉलमेंट पर काम कर रहे हैं, तो फैंस की उत्सुकता सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। अब हाल ही में फिल्म के पहले पार्ट में डॉ अस्थाना और दूसरे पार्ट में लकी का किरदार निभाने वाले अभिनेता बमन ईरानी ने भी मुन्ना भाई-3 को लेकर एक ऐसा अपडेट शेयर किया है, जिससे फैंस के चेहरे निश्चित रूप से खिल उठेंगे।

मुन्ना भाई 3 पर क्या बोले बमन ईरानी?

राजकुमार हिरानी की अधिकतर फिल्मों में अहम भूमिका निभाने वाले बमन ईरानी ने हाल ही में द राजा साब के एक इवेंट पर यह हिंट दे दी है कि वह संजू बाबा के साथ मुन्ना भाई-3 में नजर आ सकते हैं। द राजा साब के सॉन्ग लॉन्च पर बमन ईरानी ने कहा, संजय दत्त के साथ काम करना हमेशा स्पेशल होता है। मुन्ना भाई सिर्फ एक फिल्म नहीं,बल्कि इमोशन है। हम एक परिवार की तरह हैं और वह बिताए गए पल हमारे साथ पूरी जिंदगी रहने वाले हैं। मिड डे की एक खबर के मुताबिक,इस दौरान जब बमन से मुन्ना भाई 3 के प्रोग्रेस पर पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा,मुझे यकीन है कि जब सही समय और सही कहानी मिलेगी,तो मुन्ना भाई का तीसरा पार्ट जरूर बनेगा। मैंने हमेशा दिल ही दिल में ये मेनिफेस्ट किया है और उम्मीद है कि जल्द हे हम सब फिर साथ में काम करेंगे।

वक्त के साथ मजबूत हुआ है रिश्ता

संजय दत्त के साथ कई फिल्मों में काम कर चुके बमन ईरानी ने उनकी तारीफ करते हुए बताया कि संजू बाबा से उनकी बॉन्डिंग बीतते वक्त के साथ और भी मजबूत हुई है। वह सेट पर बिल्कुल एक अलग तरह की एनर्जी लेकर आते हैं। बमन ने बताया कि संजय दत्त क्रिएटिव मुश्किलों और सेट के एनवायरमेंट को बिल्कुल कम्फर्टेबल बना देते हैं। बमन ने यहां ये हिंट तो दे दी कि मुन्ना भाई की अगली फ्रेंचाइजी जरूर आएगी, लेकिन कब इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल बमन ईरानी और संजय दत्त, प्रभास स्टारर फिल्म द राजा साब में स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म पांच भाषाओं तमिल-तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम में 9 जनवरी 2026 में रिलीज होगी।

विनोद मेहरा थे पहले पति,घर से भागकर की दूसरी शादी

विनोद मेहरा सिनेमा जगत के ऐसे कलाकार थे,जो अपने प्रोफेशनल करियर के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहते थे। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि विनोद की दूसरी पत्नी रहीं अदाकारा ने घर से भागकर शादी की थी। यदि हिंदी सिनेमा के किसी ऐसे अभिनेता के बारे में जिक्र किया जाए तो जो अपने एक्टिंग करियर से ज्यादा निजी जिंदगी के मसलों को लेकर चर्चा में रहता था तो वह कोई और नहीं बल्कि विनोद मेहरा थे। 1980 में विनोद ने बॉलीवुड की एक फेमस अदाकारा संग शादी रचाई थी, जो लंबे समय तक नहीं चल सकी। 6 जनवरी यानी आज उसी अभिनेत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसकी कहानी काफी रोचक है। विनोद मेहरा संग तलाक के बाद उस एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा के एक मशहूर फिल्ममेकर संग दूसरी शादी रचाई थी, लेकिन घर से भागकर। आइए जानते हैं यहां किस अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

कौन है 70 के दशक की लेडी सुपरस्टार

इस लेख में जिस एक्ट्रेस के बारे में बात की जा रही है, उसने ग्लैमर्स की दुनिया में अपनी सादगी से हर किसी का दिल जीत लिया था। 70 से लेकर 80 के दशक में बैक टू बैक हिट्स मूवीज देकर वह अदाकारा एक वक्त पर रेखा और जया बच्चन जैसी अभिनेत्रियों से सफल मानी जाने लगीं। लेकिन दूसरी शादी के बाद उस एक्ट्रेस ने एक्टिंग को अचानक से छोड़ दिया था। दरअसल यहां जिक्र एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी का किया जा रहा है।

जी हां बिंदिया अपने जमाने में हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेज में शुमार हुआ करती थीं। उन्होंने गोलमाल,खट्टा मीठा और जानी दुश्मन जैसी कई सफल मूवीज में काम किया। बिंदिया ने पहली शादी 18 साल की उम्र में विनोद मेहरा संग की थी। लेकिन कुछ सालों बाद उनकी शादी टूट गई और तलाक हो गया। इसके बाद 1985 में बिंदिया ने फिल्ममेकर जेपी दत्ता को अपना हमसफर बनाया। चूंकि बिंदिया गोस्वामी के परिवार वाले उनकी इस शादी के खिलाफ थे तो इस कारण बिंदिया और जेपी ने घर से भागकर शादी करना मुनासिब समझा। हालांकि दूसरी वेडिंग के बाद बिंदिया ने एक्टिंग छोड़ दी और परिवार संग जीवन बितना शुरू किया।

बिंदिया की बेटी बड़ी फिल्ममेकर

बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता की एक बेटी भी है, जिसका नाम निधि दत्ता हैं। गौरतलब है कि निधि बतौर निर्माता हिंदी सिनेमा में एक्टिव हैं और जल्द ही उनकी नई फिल्म बॉर्डर 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

6 साल बाद शुरू हुई श्रद्धा कपूर की अटकी हुई फिल्म

पर्दे पर इच्छाधारी नागिन बनेंगी सिनेमा की स्त्री?

हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 से फैंस के दिलों को जीतने वाली अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने 6 साल पहले अपनी एक फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने इच्छाधारी नागिन बनने की बात कही थी। अब इस मूवी पर लेटेस्ट अपडेट आया है। बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें श्रद्धा कपूर का नाम जरूर शामिल होगा। स्त्री 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाली श्रद्धा की आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और फैंस उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करता देखने के लिए बेताब हैं। इस बीच श्रद्धा कपूर की 6 साल से अटकी हुई एक फिल्म को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है, जिसमें अभिनेत्री इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाती हुई दिखेंगी। फिल्म स्त्री 2 की सफलता के बाद अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने अगली फिल्म के चुनाव में भले ही काफी ज्यादा समय लिया हो,लेकिन अब उनका इरादा ज्यादा समय खाली बैठने का नहीं है। वह फिलहाल फिल्मकार लक्ष्मण उतेकर की फिल्म ईथा की शूटिंग कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग मार्च तक चलेगी। उन्होंने उसके बाद का भी शेड्यूल तय कर लिया है।

खेल समाचार

एस ए 20 में सनराइजर्स केप ने प्रिटोरिया को पहली बार हराया

डी कॉक-बेयरस्टो की शतकीय साझेदारी,सनराइजर्स टॉप पर

प्रिटोरिया,06 जनवरी 2026। एस ए 20 के चौथे सीजन में सेंचुरियन में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को पहली बार हराया। क्विंटन डी कॉक और जॉनी बेयरस्टो की नाबाद शतकीय साझेदारी की बदौलत टीम ने 177 रन का टारगेट महज 14.2 ओवर में बिना विकेट गंवाए हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ट्रिस्टन स्टब्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स ईस्टर्न केप 17 अंकों के साथ एक बार फिर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई। विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए क्विंटन डी कॉक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

प्रिटोरिया कैपिटल्स कॉनर एस्टरह्यूजन टॉप स्कोरर रहे

इससे पहले, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन ही बना सकी। ओपनर कॉनर एस्टरह्यूजन ने 33 गेंदों पर 52 रन बनाए,जबकि शरफेन रदरफोर्ड ने 22 गेंदों पर नाबाद 47 रन की तेज पारी खेली। इनके अलावा अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके। सनराइजर्स की ओर से एनरिक नॉर्टजे ने अपने पुराने घरेलू मैदान पर 150 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए। लुईस ग्रेगरी ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 1 विकेट झटका। एडम मिल्ने ने अंतिम से पहले ओवर में 22 रन लुटाने के बावजूद 2/36 के आंकड़े दर्ज किए,जिसमें आंद्रे रसेल का अहम विकेट शामिल रहा।

बिना विकेट खोए लक्ष्य हासिल कर लिया लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। डी कॉक ने 41 गेंदों पर 79 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं, बेयरस्टो ने 44 गेंदों में 85 रन की पारी खेली और 8 चौके व 6 छक्के जड़े। बेयरस्टो ने स्पिनर केशव महाराज के एक ही ओवर में पांच छक्के और एक चौका लगाकर 34 रन बटोरे। यह ओवर टी 20 इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ।

महिला टी20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायरः नीदरलैंड्स की कप्तान बनीं बैबेट डी लीडे

एम्स्टर्डम,06 जनवरी 2026। नीदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को आईसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर के लिए 15-सदस्यीय टीम की घोषणा की, जो 18 जनवरी से 1 फरवरी तक नेपाल में होगा। बेबेट डी लीड टीम की कप्तानी करेंगी, क्योंकि नीदरलैंड्स एक महत्वपूर्ण महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वालि फिकेशन अभियान की तैयारी कर रहा है। हेड कोच नील मैक्रे का मानना है कि टीम में अनुभव और हाल के मजबूत प्रदर्शनों का संतुलन है, जो उन्हें क्वालिफिकेशन लाइन पार करने में मदद करेगा। उन्होंने नीदरलैंड्स क्रिकेट वेबसाइट से कहा,हमने नेपाल में आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर के लिए एक अनुभवी टीम चुनी है। उन्होंने थाईलैंड में हाल ही में हुए आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 में डच टीम के प्रभावशाली प्रदर्शन के बारे में भी बात की, जहां वे फाइनल स्टैंडिंग में तीसरे स्थान पर रहीं।

मैक्रे ने आगे कहा, ÷थाईलैंड में हाल ही में हुए आईसीसी इमर्जिंग नेशंस टूर्नामेंट में कुछ मजबूत प्रदर्शन करने के बाद, टीम आईसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करने के अवसर को लेकर उत्साहित है। हाल के प्रदर्शनों ने टीम की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। डच महिलाओं ने 2025 के आखिर में कई मजबूत नतीजे दिए, जिसमें थाईलैंड में एक प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल करना शामिल है। वे नेपाल में टॉप चार में जगह बनाने और इंग्लैंड में वर्ल्ड कप का टिकट पाने के लिए एक आत्मविश्वासी दावेदार के रूप में प्रवेश कर रही हैं। ग्लोबल क्वालि फायर में बांग्लादेश, आयरलैंड, नीदर लैंड्स, नामीबिया, नेपाल, पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड, थाईलैंड, यूएसए और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। टीमों को पांच-पांच के दो ग्रूप में बांटा गया है, जिसमें आयरलैंड ग्रूप ए में है। ग्रूप स्टेज के बाद, हर ग्रुप से टॉप तीन टीमें सुपर सिक्स राउंड में आगे बढ़ेंगी, जिसमें से टॉप चार टीमें महिला टी 20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेंगी। 2026 महिला टी20 वर्ल्ड कप जून में इंग्लैंड और वेल्स में होगा और इसमें 12 टीमें 33 मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यह 2024 में बांग्लादेश और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए 10-टीम टूर्नामेंट से एक विस्तार है। आठ टीमों ने पहले ही 2026 संस्करण के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है, जिसमें मेजबान इंग्लैंड के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज,पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।

सडन डेथ रोमांच में एसजी बंगाल टाइगर्स ने एसजी पाइपर्स को हराया

रांची,06 जनवरी 2026। एसजी बंगाल टाइगर्स ने एक बार फिर अपना संयम बनाए रखते हुए स्त्र पाइपर्स को 0-0 (7-6 एसओ) से हराकर रोमांचक महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 मुकाबले में जीत हासिल की। रेगुलेशन टाइम में गोल रहित ड्रॉ के बाद सडन-डेथ शूटआउट में जीत हासिल करके उन्होंने लीग के फाइनल में जगह पक्की कर ली। अपनी पिछली मुलाकात की तरह ही, यह मुकाबला भी उसी तरह से हुआ,मैच एक बार फिर सडन डेथ तक गया और टाइगर्स ने जीत हासिल करके एक महत्वपूर्ण बोनस पॉइंट हासिल किया और फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली। यह मैच पाइपर्स के लिए सिर्फ औपचारिकता थी,क्योंकि वे पॉइंट्स टैली में अपनी बड़ी बढ़त के कारण इस मैच से पहले ही महिला एचआईएल 2025-26 के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुके थे। मैच के पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली,क्योंकि स्त पाइपर्स और श्रची बंगाल टाइगर्स दोनों ने शुरुआती हमलों के साथ एक-दूसरे का सामना किया। टाइगर्स ने शुरुआती तीन मिनट के अंदर एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन वे इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। इसके बाद एसजी पाइपर्स ने गेंद पर नियंत्रण बनाया,गेंद को तेजी से घुमाया और टाइगर्स के डिफेंस को परखने के लिए कई बार सर्कल में प्रवेश किया। दोनों तरफ शुरुआती गति और मौकों के बावजूद,कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई,और पहला क्वार्टर 0-0 से गोल रहित समाप्त हुआ। श्रची बंगाल टाइगर्स ने दूसरे क्वार्टर में स्त पाइपर्स के डिफेंस पर शुरुआती दबाव बनाया,लगातार हमले किए और एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया।

बिहार ने मणिपुर को हराकर एलीट लीग में बनाई जगह

रांची,06 जनवरी 2026। बिहार ने विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट 2025-26 के फाइनल में मंगलवार को मणिपुर के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की। इसी के साथ बिहार ने अगले सीजन के लिए एलीट लीग में जगह पक्की कर ली। इस जीत ने प्लेट ग्रुप में बिहार के पूरे दबदबे को दिखाया। बिहार ने फाइनल से पहले पांच लीग-स्टेज मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए सीजन का अंत किया। इस अभियान में भविष्य के लिए भी अच्छे संकेत दिखे, जिसमें किशोर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने दो मुकाबलों में हिस्सा लिया और 221 रन बनाए। इसमें अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शानदार 190 रन की पारी भी शामिल है।

प्लेट ग्रुप का खिताब जीतकर और प्रमोशन हासिल करने के बाद बिहार अगले सीजन से विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट ग्रूप में खेलेगा,जो टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम और बिहार क्रिकेट के लिए गर्व का पल है।

जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी मणिपुर 47.5 ओवरों में 169 रन पर सिमट गई। इस टीम के चार बल्लेबाज अपना खाता तक नहीं खोल सके। मणिपुर के लिए उलेन्याई ख्वाइराकपम ने 112 गेंदों में 7 चौकों के साथ सर्वाधिक 61 रन बनाए, जबकि फिरोजम जोतिन ने 51 रन की पारी खेली। बिहार की तरफ से शब्बीर खान ने 8 ओवरों में महज 30 रन बनाकर 7 विकेट हासिल किए। शेष 3 विकेट हिमांशु तिवारी ने अपने नाम किए। आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिहार की टीम ने 31.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम के लिए आयुष लोहारुका ने 11 चौकों के साथ 75 रन की पारी खेली। वहीं, मंगल महरौर ने 32 रन अपने खाते में जोड़े। इस बीच आकाश राज ने आयुष लोहारुका के साथ चौथे विकेट के लिए 62 गेंदों में 57 रन जुटाए। विपक्षी खेमे से बिश्वोरजित कोंथौजम, फिरोजम जोतिन, किशन थोकचोम और किशन सिंघा ने 1-1 विकेट हासिल किया।

बिलासपुर बनेगा छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन

मुख्यमंत्री साय ने प्रस्तुत किया 15 वर्षीय विकास विजन

शहरों के संतुलित,समावेशी और योजनाबद्ध विकास को लेकर सरकार प्रतिबद्ध : सीएम साय

रायपुर, 06 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार ने आज यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि आने वाले दशक में बिलासपुर राज्य का अगला ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक ने बिलासपुर के समग्र विकास के लिए एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक अभियान का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। बैठक में जिस प्रकार केंद्र और राज्य के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी दर्ज हुई,उसने यह साबित कर दिया कि बिलासपुर का विकास केवल स्थानीय मुद्दा नहीं,बल्कि छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता का विषय बन चुका है। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव,केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक अमर अग्रवाल,विधायक सुशांत शुक्ला,विधायक धरमलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी,मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह तथा विभिन्न विभागों के सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारीगण सभी एक ही मंच पर उपस्थित थे। इस संयुक्त उपस्थिति ने यह शक्तिशाली संदेश दिया कि बिलासपुर का विकास दिल्ली और रायपुर दोनों स्तरों के बीच प्रत्यक्ष समन्वय से आगे बढ़ेगा और योजनाओं की स्वीकृति, वित्तीय प्रावधान और क्रियान्वयन में गति लाने के लिए राजनीतिक तथा प्रशासनिक इच्छा-शक्ति पूरी तरह सक्रिय है।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में स्वयं बिलासपुर के अगले 10-15 वर्षों के शहरी विकास का विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल वर्तमान समस्याओं पर नहीं, बल्कि भविष्य की जनसंख्या वृद्धि, शहरी विस्तार,ट्रैफिक प्रबंधन, आवास,जल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज और समग्र नगर नियोजन पर व्यापक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 'नाली से लेकर नगर नियोजन तक' कोई भी विषय चर्चा से बाहर नहीं छोड़ा गया। यही संदेश यह स्थापित करता है कि सरकार केवल घोषणाएँ नहीं कर रही,बल्कि बारीकी से जमीन पर लागू होने योग्य योजना बना रही है। इस दृष्टिकोण ने मुख्यमंत्री की छवि एक दूरदर्शी शहरी विकास नेता के रूप में और सुदृढ़ की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी संकेत दिया कि बिलासपुर को सिर्फ एक बड़े शहर के रूप में नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के नए आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य हब विकसित किया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट,इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और निवेश के नए अवसरों के साथ बिलासपुर को मध्य भारत का प्रमुख शहरी केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले वर्षों में बिलासपुर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा,जहाँ आधुनिक नगरीय सुविधाएं, स्वच्छता व्यवस्था,सस्टेनेबल शहरी ढांचा और रोजगार सृजन के नए अवसर साथ-साथ आगे बढ़ेंगे।

इससे न केवल बिलासपुर,बल्कि पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र को नई आर्थिक दिशा मिलेगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी ने समावेशी राजनीति का स्पष्ट संदेश दिया। विधायक,महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति ने यह स्थापित किया कि बिलासपुर का विकास किसी एक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि शहर के भविष्य का सामूहिक संकल्प है। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि विकास के प्रश्न पर दलगत राजनीति को पीछे छोड़ दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। इससे यह संदेश गया कि बिलासपुर विकास रोडमैप केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने आवश्यक बजट प्रावधान और दीर्घकालिक निवेश योजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्र और राज्य समन्वय के इस मॉडल ने यह सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़ की शहरी विकास योजनाएं अब सीधे राष्ट्रीय मिशनों से जुड़ चुकी हैं। स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, हाउसिंग, नगरीय परिवहन और आधारभूत संरचना से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी, जिससे बिलासपुर को विशेष लाभ मिलेगा। बैठक के बाद मीडिया में प्रमुखता से यह संदेश उभरा कि बिलासपुर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का अगला ग्रोथ इंजन बनेगा। औद्योगिक निवेश, शहरी रोजगार, रियल एस्टेट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से यहाँ विकास की नई लहर उत्पन्न होने जा रही है। बिलासपुर के विकास का यह अभियान प्रदेश की समग्र राजनीति में भी महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। शहरी विकास, रोजगार सृजन और आधारभूत संरचना पर केंद्रित यह एजेंडा डबल इंजन सरकार की विकासोन्मुखी राजनीति की पहचान बनेगा।

बैठक में यह स्थापित कर दिया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिलासपुर का विकास केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं,बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संकल्प है। डबल इंजन सरकार की ताकत के साथ बिलासपुर अब राष्ट्रीय शहरी विकास मानचित्र पर अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

नारायणपुर में दरिंदगी...11 साल की बच्ची से रेप के बाद कुल्हाड़ी से हत्या,आरोपी गिरफ्तार

नारायणपुर,06 जनवरी 2026। नारायणपुर जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ एक 22 वर्षीय युवक ने 11 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर अपनी पहचान उजागर होने के डर से कुल्हाड़ी मार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी संजू कुमेटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह खौफनाक वारदात 31 दिसंबर की शाम को हुई, जब पूरा देश नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहा था। आरोपी संजू कुमेटी (22 वर्ष) नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ पास के एक

खेत में ले गया। वहाँ उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। जब उसे डर लगा कि बच्ची घर जाकर सब सच बता देगी, तो उसने पास ही रखे कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि 31 दिसंबर से ही उनकी बेटी घर से अचानक लापता हो गई थी। परिवार वालों ने उसे गांव और आसपास के इलाकों में काफी तलाशा,लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। घटना के चार दिन बाद,यानी 4 जनवरी को गांव के ही एक खेत में ग्रामीणों ने एक शव देखा। जब परिजन वहां पहुंचे, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई; वह लाश उनकी उसी लापता बेटी की थी। शव की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसके साथ बर्बरता हुई है। कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। डॉक्टरों की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने हत्या के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी।

5 लाख की इनामी नक्सली भूमिका ने धमतरी में किया सरेंडर

रायपुर,06 जनवरी 2026। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से सक्रिय 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली भूमिका उर्फ गीता उर्फ लता उर्फ सोमारी ने पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। वह नगरी एरिया कमेटी की सदस्य और गोबरा एलओएस कमांडर के रूप में कार्यरत थी। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमावर्ती इलाकों में संगठन की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती थी। आत्मसमर्पण के बाद शासन की नीति के अनुरूप भूमिका को 50 हजार की प्रोत्साहन राशि दी गई। वहीं पुनर्वास का लाभ भी दिया जाएगा। मूलतः ग्राम पुसनार, थाना गंगालूर जिला बीजापुर की रहने वाली 37 वर्षीय भूमिका पर शासन ने पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। लंबे समय तक माओवादी संगठन से जुड़े रहने के अनुभवों ने भूमिका को भीतर से तोड़ दिया था। संगठन के भीतर भेदभावपूर्ण व्यवहार,हिंसा पर आधारित विचारधारा और पारिवारिक व दांपत्य जीवन से लगातार वंचित रहना उसके लिए मानसिक बोझ बन चुका था। इन्हीं परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर उसने हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया।

2005 से माओवादी संगठन में रही सक्रिय

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार भूमिका वर्ष 2005 से माओवादी संगठन में सक्रिय रही। प्रारंभिक प्रशिक्षण के बाद वह वर्ष 2010 तक प्लाटून-01 में शामिल रही। इसके पश्चात उसे ओडिशा राज्य कमेटी में भेजा गया, जहां विभिन्न इकाइयों में कार्य करते हुए वर्ष 2011 से 2019 तक वह शीर्ष माओवादी नेता सीसीएम संग्राम की सुरक्षा में तैनात रही। वर्ष 2019 से 2023 के बीच उसने सीनापाली एरिया कमेटी में एरिया कमेटी सदस्य के रूप में जिम्मेदारी निभाई, जबकि सितंबर 2023 में उसे गोबरा एलओएस कमांडर बनाया गया।

इन घटनाओं में शामिल थी भूमिका : संगठन में लगातार घटती संख्या के चलते हाल के समय में भूमिका नगरी एवं सीतानदी एरिया कमेटी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय थी। अपने लंबे नक्सली जीवन के दौरान वह कई गंभीर मुठभेड़ों में शामिल रही। वर्ष 2010 में ओडिशा के पड़कीपाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़, जिसमें आठ नक्सली मारे गए, से लेकर बीजापुर, गरियाबंद और धमतरी के जंगलों में हुई अनेक घटनाओं में उसका नाम सामने आता रहा। वर्ष 2018 में बीजापुर के तिमेनार जंगल में मुठभेड़, वर्ष 2023 में गरियाबंद के ताराझार जंगल, वर्ष 2024 में धमतरी के एकावरी जंगल और वर्ष 2025 में मांदागिरी जंगल में हुई मुठभेड़ों में भी उसकी संलिप्तता रही।

कानपुर-वाराणसी फेल कमिश्नरी सिस्टम रायपुर में होगा लागू

एक ही जिले में 2 तरह की पुलिस व्यवस्था

रायपुर,06 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम 23 जनवरी से लागू होने वाला है। इसे लेकर गृह विभाग खाका तैयार कर रहा है। मंत्री परिषद की बैठक के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार नगरीय निकाय क्षेत्र (22 शहरी थाने) में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा। गांव के इलाकों (15 थानों) में अलग से ग्रामीण एसपी बिठाया जाएगा। यही सिस्टम उत्तर प्रदेश के कानपुर और वाराणसी (बनारस) में लागू किया गया था। एक ही जिले में 2 तरह की पुलिस व्यवस्था से कई व्यावहारिक दिक्कतें और समन्वय की कमी सामने आई थी। इससे अपराध भी बढ़ने लगे थे। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने एक साल बाद ही इसे वापस ले लिया और पूरे जिले में कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया। अब इसी फेल सिस्टम को रायपुर में लागू करने की तैयारी है। चर्चा है कि मध्य प्रदेश में भी इस पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय का कड़ा फैसला...आरोपी और सहयोगी को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

बलौदाबाजार,06 जनवरी 2026। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। अपहरण कर नाबालिग के साथ बार-बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी और उसके सहयोगी को अपर सत्र न्यायाधीश ने 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक भाटापारा संजय बाजपेयी ने प्रकरण के बारे में बताया कि पीड़िता के पिता ने 11.08.2024 को भाटापारा ग्रामीण थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लड़की 10.08.2024 को सुबह 8.00 बजे घर से स्कूल जा रही हूं कहकर निकली थी, जो अभी तक वापस घर नहीं लौटी है, जिसका आसपास व रिश्तेदारों में पता किया गया, कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट पर थाना द्वारा गुम इंसान दर्ज कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अन्यत्र भगा ले जाने की शंका पर अपराध कायम कर प्रार्थी व गवाहों का कथन दर्ज किया गया।

निष्क्रिय बिजली उपभोक्ताओं को पॉवर कंपनी ने दी राहत

लागू हुई समाधान योजना,बकाया चुकाने पर मिलेगा नया कनेक्शन

रायपुर,06 जनवरी 2026। अलग-अलग वजहों से लंबे समय से निष्क्रिय पड़े बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने समाधान योजना लागू की है। इस योजना के तहत वर्षों से लंबित बिजली बिलों के भुगतान की सुविधा प्रदान की जाएगी,जिससे निष्क्रिय उपभोक्ता पुनः अपनी संपत्ति में नया बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। योजना के क्रियान्वयन में अधिकृत मीटर रीडर उपभोक्ताओं की सक्रिय रूप से सहायता करेंगे।

प्रदेश में पौने तीन लाख निष्क्रिय उपभोक्ता : पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अनुसार प्रदेश में ऐसे पौने तीन लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनके बिजली बिल लंबे समय से

बकाया हैं। बकाया राशि के कारण डीआरए (ड्यूज रिकवरी एक्ट) के तहत पहले नोटिस जारी किया गया, फिर कनेक्शन काटा गया और भुगतान नहीं होने पर घरों एवं प्रापर्टी से बिजली मीटर निकाल लिए गए। वर्तमान में प्रदेश में 2 लाख 76 हजार निष्क्रिय उपभोक्ता दर्ज हैं, जिनसे कंपनी को लगभग 175 करोड़ रुपये की वसूली शेष है।

समाधान योजना का इस तरह मिलेगा लाभ : कई मामलों में उपभोक्ता का निधन हो चुका है या संबंधित संपत्ति बिक चुकी है। ऐसे प्रकरणों में भी जब तक उस भूमि या प्रापर्टी पर कोई बिजली बकाया दर्ज रहता है, तब तक नया कनेक्शन नहीं दिया जाता। इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान योजना लाई गई है, ताकि बकाया राशि का निपटान कर उपभोक्ताओं को दोबारा विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

मीटर रीडरों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि : योजना के अंतर्गत प्रदेशभर में नवीन मीटर रीडर योजना के तहत कार्यरत स्वतंत्र मीटर वाचक निष्क्रिय उपभोक्ताओं से संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने में सहयोग करेंगे। इस कार्य के बदले पॉवर कंपनी द्वारा निष्क्रिय उपभोक्ताओं से वसूल की गई राशि का 10 से 15 प्रतिशत तक प्रोत्साहन राशि मीटर रीडरों को दी जाएगी। वितरण केंद्रों द्वारा निष्क्रिय बकायादारों की प्रमाणिक सूची संबंधित मीटर रीडरों को उपलब्ध कराई जाएगी। अपने नियमित मीटर रीडिंग कार्य पूर्ण करने के बाद हर माह 15 तारीख से मीटर रीडर बकाया वसूली की प्रक्रिया के लिए उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे।

कवासी लखमा से मिलने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे पूर्व सीएम बघेल

भाजपा पर साधा निशाना, कही ये बात...

रायपुर,06 जनवरी 2026। शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। करीब एक साल से जेल में बंद लखमा से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों और भाजपा पर तीखा हमला बोला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कुछ लोग यह प्रचार कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे को छुड़ा लिया, लेकिन अगर ऐसा होता तो उनका बेटा जेल ही क्यों जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने अब तक कवासी लखमा के जवाब पर रिप्लाई तक दाखिल नहीं की है। बीजेपी के मंत्री नेता आज गलती से सच बोल रहे हैं। निर्दोष लखमा को 1 साल ED-EOW ने जेल में बंद किया हुआ है।

भाजपा के नेता भी इस बात को मान रहे है। सवाल यह है तो कार्रवाई क्यों? एफआईआर क्यों? कुछ बोलते हैं कि बेटे को छुड़ा लिया। अगर मेरा चलता तो वह जेल क्यों जाता? भाजपा को घड़ियाली आंसू बहाना बंद करना चाहिए। बता दे कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद भाजपा ने सवाल खड़े किए। भाजपा नेताओं का कहना है कि शराब घोटाले जैसे गंभीर मामले में भूपेश बघेल के बेटे को जमानत मिल जाती है।

8 जनवरी को रायपुर आएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट

रायपुर,06 जनवरी 2026। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 8 जनवरी को एक दिन के दौरे पर रायपुर आने वाले हैं। पार्टी के मुताबिक,इस दौरान वे प्रदेशभर में मनरेगा को लेकर चल रहे आंदोलन की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही हाल ही में नियुक्त किए गए जिलाध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि, सचिन पायलट इस दौरे के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों पर भी फोकस करेंगे। नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की भूमिका, जिम्मेदारियों और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि, जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर भी रूपरेखा तय की जा सकती है। कांग्रेस के लिए यह दौरा अहम माना जा रहा है, क्योंकि

मनरेगा को लेकर पार्टी ने प्रदेशभर में आंदोलन छेड़ रखा है। इससे पहले, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 26 नवंबर को दो दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ आए थे। उस दौरान उन्होंने प्रदेशभर में चल रहे स्ट्रक्अभियान की समीक्षा की थी और संविधान बचाओ दिवस से जुड़े प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। पायलट 26 नवंबर को रायपुर पहुंचे थे और वहां से सीधे धमतरी के लिए रवाना हुए थे।

रायपुर में 4 मेडिकल संचालक और एमआर गिरफ्तार नशीली टेबलेट सप्लाई सिंडिकेट का पर्दाफाश

रायपुर,06 जनवरी 2026। पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान 'ऑपरेशन निश्चय' के अंतर्गत प्रतिबंधित नशीली टेबलेट में लिप्त अपराधियों की बदलती कार्यप्रणाली पर त्वरित और सटीक कार्यवाही करते हुए सप्लाय चैन सिंडिकेट का भाण्डाफोड़ कर थाना पुरानी बस्ती में 4 मेडिकल दुकान के संचालक और एक एमआर सहित 5 आरोपियों को 17,808 नग प्रतिबंधित नशीली टेबलेट अल्प्राजोलम एवं स्पासमों के साथ गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में चारपहिया टाटा सफारी वाहन क्रमांक सी जी 04 क्यू 0513 एवं 05 नग मोबाइल फोन को भी जप्त किया गया है। सम्पूर्ण जप्त मशरूका की कुल अनुमानित कीमत 01

करोड़ रूपये है। आरोपियों के विरुद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 10/26 धारा 21(सी), 29 नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आईजी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के दिशा-निर्देश में संचालित ऑपरेशन निश्चय के लगातार दबाव के कारण अब प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के तस्कर एवं सप्लार अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर नए पैटर्न अपना रहे हैं। रायपुर पुलिस द्वारा इंटेलिजेंस-ड्रिवन, एंड-टू-एंड विवेचना और माइक्रो-लेवल सर्विलांस अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को सूचना प्राप्त हुई कि थाना पुरानी बस्ती क्षेत्रांतर्गत कुशालपुर स्थित रत्ना मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा बिना किसी वैध कागजात के अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री किया जा रहा है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त मेडिकल स्टोर में अपना प्वाईंटर भेजकर टेस्ट पर्चेस कराया गया, जैसे ही संचालक द्वारा पुलिस के प्वाईंटर को बिना किसी कागजात के अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट बिक्री किया गया वैसे ही पुलिस टीम द्वारा दुकान में रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति उपस्थित था जिसने पूछताछ में अपना नाम कान्हा कृष्ण कश्यप उर्फ सूरज होना बताने के साथ ही स्वयं को मेडिकल दुकान का संचालक होना बताया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)